

2507
17/3/06



असंशोधित

- 9 MAR 2006

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2-कार्यवाही-प्रश्नोत्तर रहित)

लाख का है । ये शेष पथांश कि०मी० १८६ से १९० के लिए इतना का प्राक्कलन तैयार कर और राज्य उच्च पथ मुख्य अभियंता, उपभाग के पत्रांक-१५४ अनु० के द्वारा दिनांक-०७.०२.२००६ को पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किया जा चुका है । प्राक्कलन स्वीकृति के उपरान्त शेष पथांश में भी कार्य प्रारम्भ की जाएगी ।

श्री शोभाकान्त मंडल: अध्यक्ष महोदय, लक्खीसराय से शुरू करके पहला फेज जो इन्होंने बताया, उससे हमारे प्रश्न का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे ध्यानाकर्षण का कोई सरोकार नहीं है । हमारा सरोकार जो प्राक्कलन की स्वीकृति है, जो होने वाली है, उससे है और इसके नहीं होने से, इस सड़क के नहीं बनने से, ये दो राज्यों की सीमा का सड़क जिस पर चलते हुए लोग अपनी इष्टदेव को समझता है और जैसे ही लोग झारखंड से बिहार घुसते हैं तो समझ जाते हैं कि हम दूसरे राज्य में आ गये हैं । अब नयी सरकार आयी है । कम-से-कम यह परिवर्तन तो दिखायी पड़ना चाहिये कि यह सरकार के समय में यह सड़क बन गया, वित्तीय वर्ष २००६-०७ में । यह आश्वासन आप हमें दें ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, मंत्री: आप जब इतनी उम्मीद रख रहे हैं हमसे, हम बहुत सुक्रगुजार हैं, पूरा यही सरकार करेगी इसलिए ठीक उम्मीद आपने रखा है और यह ५८९ लाख की योजना से तो संबंध आपका है, ४१७ से अपने को अलग कर रहे हैं, आप । हालांकि, हम ४१७ और ५८९ लाख दोनों को साथ मिला करके हम निर्माण करेंगे लेकिन हम ५८९ लाख की जो बात है, इसको भी हम भारत सरकार से जल्द से जल्द स्वीकृति प्राप्त करके हम काम लगावेंगे । इस साल के अन्दर में, इस निविदा में हो जायेगा ।

श्री रामदास राय: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि जिन पथों के बारे में, वह इसे ध्यानाकर्षण से संबंध नहीं रखता है । मूल बात है पीरपैती से मिर्जा चौकी तक जो ९ कि०मी० है । ९ कि०मी० पथ के निर्माण के लिए आपने प्राक्कलन भारत सरकार को भेजा है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि आप प्राक्कलन की स्वीकृति करा करके अगले वित्तीय वर्ष में इस कार्य को पूरा करायेंगे कि नहीं ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, मंत्री: मैं शायद यही बताया और आपने ध्यान नहीं दिया, रामदास बाबू । कभी कभी हम आपके ध्यान से हट जाते हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है । यही बात मैंने, जो बात आप कर रहे हैं वही बात मैंने बतायी है । अभी कि वह ५८९ लाख का जो योजना है, उसको भी भारत सरकार को हम भेज चुके हैं और जल्द से जल्द उसकी स्वीकृति प्राप्त करके हम इस वर्ष में काम लगायेंगे ।

अध्यक्ष: अब ध्यानाकर्षण समाप्त हुए ।

सभा की बैठक २.०० बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(स्थगन)

अंतराल के बाद

[इस अवसर पर मा० अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

अध्यक्ष: अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

श्री रामदेव राय: अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी कुछ देर में स्वास्थ्य संबंधी मांग पर चर्चा होगी लेकिन अभी तक स्वास्थ्य संबंधी प्रतिवेदन नहीं बांटा गया है । महोदय, आज ही नहीं पिछले मांगों पर प्रतिवेदन समय पर नहीं बांटा था ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष: माननीय मंत्री प्रभारी स्वास्थ्य ।

श्री चन्द्रमोहन राय, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

" स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग " के संबंध में ३१ मार्च, २००७ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए १०,८३,३०,१८,०००/- (दस अरब तेरासी करोड़ तीस लाख अठारह हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य, श्री जगदानन्द सिंह, डॉ० अच्युतानन्द, श्री लालबाबू राय, श्री रामदेव राय, श्री रामदास राय एवं श्री प्रदीप कुमार जोशी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । इनमें पांच जेनरल नेचर का कटौती प्रस्ताव है जिस पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं । मैं उसी को लेता हूँ ।

माननीय सदस्य, श्री जगदानन्द सिंह, डॉ० अच्युतानन्द, श्री लालबाबू राय, श्री रामदेव राय एवं श्री रामदास राय के कटौती प्रस्ताव क्रमांक ४६,४७,४८,४९ एवं ५० व्यापक है ।

श्री जगदानन्द सिंह का प्रथम प्रस्ताव है अतः माननीय सदस्य, श्री जगदानन्द सिंह अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री जगदानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"इस शीर्षक की माँग १०/- (दस) रुपये से घटायी जाय ।"

राज्य सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

(व्यवधान)

अफसोस कि इस जगर पर आठ वर्ष रहे तो स्वयं अपने से प्रश्न नहीं कर पाये कि क्यों नहीं हम प्रस्ताव मूव करें । महोदय, मेरी जगह पर आदरणीय, श्री शकुनी चौधरी जी बातों को रखेंगे ।

श्री शकुनी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जो प्रतिवेदन आना चाहिए था वह प्रतिवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ । तीन महीना में १०० दिन में इन्होंने कोई कार्य किया है । अगर कार्य कुछ किया रहता तो निश्चित प्रतिवेदन आ जाता लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया ।

(व्यवधान)

लेकिन फिर भी पिछली सरकार की उपलब्धि सिर्फ मैं बता देता हूँ शायद सरकार को कुछ ज्ञान आ जाय तो मुझे खुशी होगी । मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो जन्मदर १९८८ में ३७.३ प्रतिहजार था उसको २००५ तक में ३१.९ प्रति हजार किया । जो ६ परसेंट की कमी है । मृत्युदर जो १९९० में १२.६ प्रतिहजार था वह मृत्युदर ८.१ प्रति हजार कर दिया जो ४ परसेंट से कम है । और इसका भारत सरकार में अगर देखा जाय तो जन्म दर है ३१.३ प्रति हजार और इसका २००५ में २५.८ प्रति हजार । ६.५ का इन्होंने कम किया है तो मैंने ४ परसेंट का और इन्होंने ६ परसेंट कम किया है । मृत्युदर जो ९० का ६.६ और भारत सरकार का है १०.८ प्रति हजार ।

क्रमशः

श्री शकुनी चौधरी :क्रमशः

भारत का है १०.८ प्रति हजार, मृत्यु दर है २००५ में बिहार का ८.८ प्रति हजार और भारत का है ८.५ प्रति हजार जो नेशनल ऐवरेज से भी कम है । नवजात शिशु दर ९० में ९७ प्रति हजार और भारत का है ९४ प्रति हजार । नवजात मृत्यु दर २००५ में हमने किया है ६२ प्रति हजार जो ३५ प्रति हजार घटा है, भारत का है ९४ प्रति हजार और ६८ प्रति हजार जो २६ प्रतिशत कम है, हमारा ऐचीवमेंट देखा जाय ।

महोदय, डिक्लाइन का दर ९६ में ८.८ प्रतिशत था और २००५ में १.४ प्रतिशत हो गया जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है और यह हुआ कैसे, आप अंदाजा करेंगे अध्यक्ष महोदय, कि श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार ने जो ५०० रुपये प्रति गरीब महिला को फर्स्ट बच्चे में गर्भवती महिलाओं को देने का निर्णय लिया और दूसरे बच्चों में ३०० रुपये देने का निर्णय लिया उससे विकलांगता दर घटी है । आप देखेंगे डायग्नोस्टिक सेंटर पटना, मुजफ्फरपुर प्रमंडल को छोड़ कर बाकी सभी में किया गया था और पटना और मुजफ्फरपुर का हमने आरा और मोतिहारी में किया था, यह सारा प्रमंडलीय स्तर पर डायग्नोसिस सेंटर इसलिये बने थे कि गरीब गुरबा जो डायग्नोसिस कराने के लिये पटना आते हैं और पटना नहीं आने के लिये सभी कमिश्नरी में यह किया गया था, यह सभी कमिश्नरी में रज किया गया था ।

श्री भोला सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष : क्या है ?

श्री भोला सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय शकुनी चौधरीजी, माननीय सदस्य श्री जगदानंद सिंह के कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं, यह कोई अपनी सरकार की उपलब्धियों पर नहीं बोल रहे हैं, जो प्रस्तुत है कटौती प्रस्ताव उसपर बोलें, सरकार की आलोचना करें, उनकी त्रुटियों की आलोचना करें, वह अपनी सरकार की उपलब्धियां क्यों बता रहे हैं ?

श्री शकुनी चौधरी : भोला बाबू की आदत है बीच बीच में टोकने की । मैं इसलिये बताना चाहता था ।

श्री भोला सिंह : यह आदत आपसे ही सीखी है ।

श्री शकुनी चौधरी : यह दो-दो करोड़ सभी डायग्नोस्टिक सेंटर के उसके सामानों की खरीद के लिये ही दे दिया लेकिन आज तक एक भी डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं चला पाये और न उसमें खरीद हो सकी किसी इक्विपमेंट के लिये, इसलिये कटौती प्रस्ताव बिल्कुल सही हुआ है ।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, आपरेशन थियेटर बनाया था मैंने, आंख आपरेशन थियेटर, जहां जहां मकान करना था वह सब जगह बन कर तैयार है लेकिन आपरेशन थियेटर के लिये जो मशीन खरीदनी थी वह नहीं खरीदी गयी है जबकि पैसा भी दे दिया गया है ।

मंत्री महोदय से इतना ही कहूंगा कि बच्चा ही सरकार है, अभी पैदा ही हुई है बहुत दिन लगेंगे समझने में और नहीं चाहता था कि कोई शिकायत करूं लेकिन मैं आग्रह करता हूं कि आप चीजों की सुविधा गरीबों को प्रदान कर दी जाय ।

श्री भोला सिंह : सरकार न जन्म लेती है, न मरती है ।

श्री शकुनी चौधरी : गरीबी रेखा से जो लोग नीचे स्तर के थे उसके लिये सरकार का निर्णय था, भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर दोनों ने एक कोष बनाया और उसके लिये २.५ करोड़ बिहार ने भी दिया और १.५ करोड़ भारत सरकार ने भी दिया, यह सारे पैसे गरीबों का पड़ा हुआ है, गरीब की हितैषी सरकार बोलते हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो गरीब हितैषी सरकार है वह जो हमारे यहां इतनी बड़ी राशि जिसको हमने ५० लाख तक तो खर्च किया लेकिन दुर्भाग्य है कि जो क्राईटेरिया है उसमें है कि गरीबी रेखा का सर्टिफिकेट सिविल एस०डी०ओ० देगा ।

....क्रमशः

टर्न-२२/राजेश/९.३.२००६

श्री शकुनी चौधरी, क्रमशः- और फिर जिला और बोर्ड के माध्यम से वह यहाँ पर आयेगा तभी हम उसपर विचार करेंगे, हम आपसे और मंत्री जी से भी कहेंगे इसको सरलीकरण करने के लिए, जो डायरेक्ट गरीब कैंसर से पीड़ित है तथा तरह-तरह के असाध्य बिमारियों से ग्रस्त हैं, उनको तत्काल मदद मिलने लगे और सरकार की तरफ से मदद मिले ।

अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में जो भर्ती होते थे मरीज, हमने उस समय ऐतिहासिक निर्णय लिया था, उस समय की बिहार सरकार ने निर्णय लिया था, पहले तीन रुपया ५५ पैसे अस्पतालों में मरीजों को भोजन मद में मिलता था, जो अस्पतालों में भर्ती होते थे, लेकिन हमारी सरकार ने उस समय निर्णय लिया था कि इसको बढ़ाया जाय और हमारी सरकार ने उसको १० रुपया कर दिया था और फिर उसको १० रुपये से बढ़ाकर हमारी सरकार ने २५ रुपया कर दिया था, यह हमारी सरकार ने निर्णय लिया था, लेकिन उसको भी यह सरकार कार्यान्वित नहीं कर पायी है, इसलिए कटौती प्रस्ताव बहुत आवश्यक था ।

अध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि एम्स की तर्ज पर यहाँ एक अस्पताल बनना था, हमने बहुत जोर लगाया था कि आई०जी०आई०एम०एस० में जहाँ १०० एकड़ जमीन है, इसको ही उन्नत कर दिया जाय, लेकिन उस समय केन्द्र में एन०डी०ए० की सरकार थी, एन०डी०ए० की सरकार ने बिना हमारी सूचना के, बिना बिहार सरकार के कोई जानकारी के, महामहिम उप-राष्ट्रपति जी को इसका शिलान्यास के लिए ले आये, इसलिए कि उस समय चुनाव का वक्त था, चुनाव का फायदा इनको उठाना था और जब मैं इसका रेकॉर्ड देखने लगा, तो मैंने पाया कि यह न तो स्वीकृत था और न ही कोई आवंटन था और उसके पहले ही इन्होंने इसका शिलान्यास करा दिया और वह शिलान्यास ऐसा हुआ है अध्यक्ष महोदय कि आज वह विरान इसी तरह पड़ा हुआ है, मुझे तो शर्म आ रही है स्वास्थ्य विभाग पर । अध्यक्ष महोदय, महामहिम उप-राष्ट्रपति जी से जिसका शिलान्यास कराया गया हो और आज वह विरान पड़ा हुआ हो, इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात हो सकती है, इसलिए इस सरकार को इन सभी बातों पर आज ध्यान देने की जरूरत है ।

अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से आप यक्ष्मा के संबंध में देखेंगे । जहाँ अध्यक्ष महोदय, १९९० में ४०.२ प्रति दस हजार में लोग ग्रसित थे, फिर २००५ में इसको घटाकर ४.७ प्रति दस हजार हो गया, यह कितनी बड़ी उपलब्धि पूर्व की सरकार ने किया था कि १९९० में १०० में ३० लोगों का मुफ्त में यक्ष्मा का इलाज चलता था, उस समय १०० में ३० आदमी यक्ष्मा से बचते थे, लेकिन हमने जब इसमें डॉट सिस्टम लगाया तो उसमें १०० में ८५ लोगों को बचाना शुरू किया, इतने लोग बचने लगे, यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी । हमारी सरकार के समय में कोई भी आदमी यक्ष्मा से मर नहीं सकता था, ऐसा प्रबंध हम लोगों ने किया था, इस बात का मंत्री जी आप पता लगा लेंगे, इसको देखेंगे तो आपको सारी वस्तुस्थिति की जानकारी मिल जायेगी ।

उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, जो नये जिले थे, जहाँ जिला अस्पताल सैंक्सन नहीं था, मैंने उन नये जिलों में जिला अस्पतालों को सैंक्सन किया और सभी नये जिलों के लिए ६ करोड़ ५२ लाख रुपया जो सैंक्सन हुआ था, वह सभी सैंक्सन हमारी सरकार के द्वारा ही किया गया था और यह इसलिए किया था कि जितने नये जिले बने थे, उसमें न तो कोई जिला अस्पताल था और न ही सिविल सर्जन का आवास था और उस समय मैंने ही दोनों चीजों की स्वीकृति दी थी, जिसमें ६ करोड़ ४२ लाख की लागत से जिला अस्पताल बनाना था और चार करोड़ ९१ लाख की लागत से सिविल सर्जन का आवास वगैरह बनेगा ।

क्रमशः

श्री शकुनी चौधरी (क्रमशः): अभी तक इन्होंने ९० दिन के शासन काल में चालू भी नहीं किया है- मुझे बहुत दुःख होता है । इसका दो बार छिड़काव होना चाहिए था गरीबों को बचाने के लिए, खासकर कालाजार रोकने के लिए फरवरी और जून महीना में छिड़काव होना चाहिए था । फरवरी में मैंने देखा कोई छिड़काव नहीं हुआ, जून में भी कोई छिड़काव नहीं हुआ । मच्छरों की तायदाद बढ़ गयी है , कालाजार का भारी प्रकोप हो गया है।

(सदन में आवाज- अभी जून माह आया कहां है, क्या पिछले जून माह की बात कह रहे हैं)

हमलोगों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था ऐड्स को रोकने के लिए और हमारी सरकार इस पर तत्परता दिखलाई और इतिहास साक्षी है, हमने जो कार्य कर दिया, हमारी सरकार मुस्तैद रही है । स्कूल कॉलेज ही नहीं मैंने यहां तक कह दिया कि माननीय सदस्यों का ब्लड जांच करायी जाये लेकिन बाद में बहुत से माननीय सदस्यों ने आग्रह किया तो मैंने कहा कि चलो इसको छोड़ देते हैं । इसका फायदा क्या हुआ, आप देखेंगे हुजूर, — ४ करोड़ लोगों की आबादी ग्रसित हुई है, पूरे दुनिया में और ५० लाख से अधिक लोग दुनिया में मर चुके हैं । ५० लाख से अधिक और हमारे यहां अगर १ लाख लोग पूरे देश में हैं तो हमारे यहां सिर्फ ३५०० लोग ग्रसित होते हैं, यह फाइनली डिजीजन नहीं हैं । अभी तक १५२ ही लोग उस बीमारी से पीड़ित हैं -१५२ आदमी ही । ये बिहार से बीमारी नहीं आयी है । जो लोग दिल्ली, मद्रास, मुम्बई में काम करते थे उनके साथ यह बीमारी आयी । बिहार ने इतिहास कायम किया है । एक भी ऐड्स की बीमारी बिहार में नहीं हुए हैं, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है । सबसे बड़ी चीज देखेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि ए०सी०पी० डाक्टरों के बीच लागू नहीं होने से जितने आई०ए०एस० अफसर हैं, वे उनको गुलाम बनाकर रखे हुए हैं, ए०सी०पी० का प्रमोशन नहीं देते हैं ए०सी०पी० के तहत प्रमोशन नहीं देंगे १९७९ से आज २००५ हैं डाक्टरों को जब प्रमोशन नहीं दीजियेगा, तो काम करने की शक्ति घट जायेगी । इसलिए, ^{जिन} डाक्टरों, जिन लोगों की हमने स्वीकृति दी है, ऐसे डाक्टरों को ए०सी०पी० के तहत प्रमोशन दीजिये । आप देखेंगे - २-३ बातें अभी आयी हैं भ्रुण हत्या के बारे में । भ्रुण हत्या हमें शर्म से झुका दिया है । आपकी सरकार में इस तरह की बातें हो रही हैं । हमारी सरकार के समय में कोई भ्रुण हत्या नहीं करायी जाती थी। अल्ट्रा साउण्ड के माध्यम से भ्रुण हत्या की बातें अखबार में आयी हैं , उसमें कहा गया है कि पूरे देश में हमारे जो डाक्टरर्स हैं, जो महिला डाक्टरर्स हैं, उसमें नाम दिया हुआ है ओर दो-दो बार राष्ट्रपति एवार्ड प्राप्त किये हुए डा० मंजुगीता मिश्रा का भी नाम आया है - पैसा के लिए क्या-क्या कुकर्म किया जाता है । इस कारण बेटी की संख्या घटती जा रही है। इसपर सरकार क्या कार्रवाई करेगी सरकार जब जबाब दे तो बतलाये ।

(व्यवधान)

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी चीज में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते हैं कि जिनसे गलती होगी, उनको हम बख्सेंगे नहीं । मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि पोंड मशीन की खरीद हुई थी, इसकी दो करोड़ से अधिक लागत है । इस मशीन को कैंसर जांच करने में उपयोग किया जाता है । उसको खरीद करने में कितनी बड़ी धांधली हुई है, इसकी भीजिलेंस ने जांच कर ली है (क्रमशः)

श्री शकुनी चौधरी (क्रमशः) - इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। आप दोनों मुख्यमंत्री को देख लीजिये कि क्या स्थिति है। सरकार कहती है कि हम स्वच्छ है। तो क्या स्वच्छ है जरा यही बता दीजिये ? अभी दूसरे लोगों का भी रिपोर्ट आ गया है। मेरे पास पूरा रिपोर्ट है। अगर आप देखना चाहेंगे तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन उस पर भी जब जांच हो गयी है तो उस पर कार्रवाई कीजिये ।

श्री भोला सिंह- अध्यक्ष महोदय, क्या यहां गलत बात कही जा सकती है ?

श्री शकुनी चौधरी - गलत नहीं है पूरा पेपर है।

अध्यक्ष - गुजरात हाई कोर्ट ने उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध भी लगाया है।

व्यवधान

श्री चन्द्र मोहन राय,मंत्री - कहीं भी मुख्यमंत्री पर आरोप नहीं है। यहां गलत बयानी नहीं चलेगी। इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष - वह शब्द नहीं जायेगा।

व्यवधान

श्री शकुनी चौधरी हम यहां की बात कर रहे हैं, यह आपके अंडर में हैं।

अध्यक्ष - माननीय सदस्य, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शकुनी चौधरी- महोदय, हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं। जितने भी बड़े एक्सीडेंट होते थे उसके लिये हमने एक ट्रौमा सेंटर का प्रस्ताव किया गया था। ट्रौमा सेंटर बिक्रम में बना है। लेकिन न तो उसके लिए पोस्ट सेंक्शन कर सके हैं, न उसके लिए मशीन खरीद सके हैं जिससे ट्रौमा सेंटर चालू हो सके। उसके साथ छपरा में, मुंगेर में ट्रौमा सेंटर का भी प्रस्ताव था, उसका भी सेंक्शन हमको लगता है कि आ गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

...

श्री राम सुन्दर राम कनौजिया - अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग के मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग में मैं ३० सालों तक नौकरी किया हूं और मैं मेडिकल अफसर भी रह चुका हूं। मैं प्रोफेसर भी रह चुका हूं। मैंने विदेशों में उच्च शिक्षा ली है। मैं आपको कंपरेटीव चार्ट दे सकता हूं कि बिहार के स्वा० शिक्षा का क्या हाल है, पूरे हिन्दुस्तान का क्या हाल है। जब बिहार की चिकित्सा शिक्षा और स्वा०विभाग को देखता हूं तो मुझे लगता है कि एलीफेंट एण्ड द सेवेन ब्लाइंड मैन की कहानी मुझे याद आती है। महोदय, हमलोगों ने बहुत तीक्ष्ण रूप से देखा है कि कैसे स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था बिगड़ती रहती है। विगत १५ सालों की विरासत के रूप में हमलोगों को मिला है। शकुनी बाबू का जून महीना आज ही पास हो गया जब कि तीन-चार महीना बाकी है।

व्यवधान

कुछ तो सोचकर बोलिये। जब मैं स्वास्थ्य विभाग के बजट की ओर देखता हूं तो बजट के लिए सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बजट में बढ़ोतरी की है।

क्रमशः

टर्न-25/सत्येन्द्र/9-3-06

श्री आर०आर०कनौजिया(कमशः)महोदय,बिहार में 42.6 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।अभी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी बाबू ने जिन बातों की चर्चा की, हमारे माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं वो ईमानदारी पूर्वक देखें कि धरातल पर कितनी सच्चाई है? महोदय,पिछले पन्द्रह वर्षों में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने क्या किया ? इन पन्द्रह वर्षों के बाद स्वास्थ्य की जो स्थिति इस सरकार को विरासत में मिली है, आप देखेंगे, चिकित्सकों पर कितना अत्याचार हुआ है।इनके शासनकाल में चिकित्सकों पर जितना प्रोसिडिंग चला,जितना ससपेंसन का काम किया गया, 6-6 वर्षों तक उनको सैलरी तक नहीं मिला, पूरा स्वास्थ्य महकमा आई०ए०एस० के शिकंजा में चला गया, वहां के डायरेक्टर इन चीफ को गुलाम की तरह काम कराया गया ,स्वास्थ्य निदेशालय की स्थिति बिल्कुल ही जर्जर हो गयी है,जिन चिकित्सक परसन से आप काम लेंगे और उनको अगर डिमोरलाईज करते रहेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर अच्छाई की कल्पना आप उनसे नहीं कर सकते हैं।स्वास्थ्य विभाग में किरानीखाना से लेकर संयुक्त सचिव,आयुक्त मंत्री तक की मिलीभगत रहती है।ये लोग पन्द्रह सालों में स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। महोदय अब आप देखेंगे, हमारी सरकार इसे कितनी अच्छी ढंग से चलायेगी।हमारी सरकार जो सुशासन की बात करती है, निश्चित रूप से रास्ते पर लायेगी, तब हमारे माननीय सदस्य इसे देखेंगे कि कैसे स्वास्थ्य विभाग चलता है? महोदय,बातें जितनी भी की जाय वह कम होगी, कल कृषि पर चर्चा हो रही थी, आप देखेंगे जो मजदूर थ्रेसर चलाकर हमलोगों को खाने का अन्न देता है जब उसका हाथ थ्रेसर में कट जाता है तो मालिक उसे अस्पताल लाकर छोड़ देते हैं, पी०एम०सी०एच० में छोड़कर उसको चले जाते हैं।अब डॉक्टर भी सदन में आ गया है। अब आप लोगों का मानसिक इलाज भी होगा। महोदय,मैं कह रहा था जो मजदूर हमलोगों को भोजन देते हैं उनका भी केयर नहीं किया जाता है। दुर्घटना होने पर उनको अस्पताल में लाकर रख दिया जाता है। सच्चाई है कि वहां का यूनिट इंचार्ज के माथे वैसे लोग पड़े रहते हैं ।डॉक्टर लोग परेशान होकर किसी तरह से चिकित्सा का कार्य करते हैं।महोदय,पद्धति ही यहां घ्वस्त हो चुकी है, मंत्री, आयुक्त कोई विगत पन्द्रह सालों में ठीक से काम नहीं किये,डॉक्टरों को ससपेंड करने के अलावा कोई काम पिछली सरकार में नहीं किया गया। महोदय,जब किसी को दुर्दिन आता है तो उसे डॉक्टर ही ठीक करता है उसका बेटा,बहु कोई नहीं काम आता है। वैसे डॉक्टर जो काम नहीं करते हैं, उनको आप ससपेंड कर दीजिये, निकाल दीजिये लेकिन उनकी कठिनाईयों पर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए।महोदय,एक चिकित्सक के रूप में मैं सरकार को सलाह दे रहा हूँ कि यह जो स्वास्थ्य की जर्जर स्थिति है उसको ठीक करने का जो उपाय है मैं उसे बतलाना चाहता हूँ । पहला स्वास्थ्य जीवन बीमा यहां लागू किया जाय। इसे मेडिकल हेल्थ इश्योरेंस कहा जाता है, यह आंध्र प्रदेश,महाराष्ट्र,दिल्ली सहित कई राज्य इसे लागू करने जा रही है।(कमशः)

डा०आर०आर०कनौजिया : महोदय, आम जनता के लिए यह बीमा बनना बहुत जरूरी है । महोदय, एक निश्चित इंतजाम होना चाहिए जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाए और जो लोग गरीबी रेखा से उपर हैं उनको अंशदान और अंशदान द्वारा स्वास्थ्य सेवा का बीमा बनाया जाए ।

दूसरा महत्वपूर्ण बात है महोदय कि हमारे सभी माननीय विधायक इस सदन में बैठे हुए हैं । प्रत्येक विधायक के यहां प्रतिदिन अनेक मरीज आते हैं और इलाज के लिए पैसा मांगते हैं जो क्षेत्र के होते हैं । हरेक बार, किसी भी विधायक को हरेक बार पैसा देने के लिए पैसा नहीं रहता है । कोई एक बार, दो बार, तीन बार मदद कर दिया लेकिन महोदय, यह संभव नहीं है ।

महोदय, क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार एक करोड़ का आवंटन किया गया, उसी प्रकार मैं सरकार से इसी सत्र से मांग करता हूं कि हरेक विधायक को कम-से-कम पचास हजार या एक करोड़ रूपया दिया जाए और यह पैसा जहां पर एक इंस्ट्रुमेंट रहे, सारी दवा रहे, सरकार सारा सब कुछ और विधायक के रिकोमेंडेशन पर उनको दिया जाए। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जितने लोग चिकित्सा लेने का काम करते हैं वह कहीं से भी ज्यादा है । मरीज जब दुर्घटना के बाद आता है, उसकी जान जब बचा दिया जाता है और जब वह जिन्दा हो जाता है तो सुबह में पूछता है कि कौन बढ़िया डाक्टर है । तो महोदय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का धज्जी उड़ाने वाले लोग, चाहे प्रेस हो या नेता हों, लेकिन आधी रात में जब किसी की जान बच जाती है और हर्ट-अटैक होता है तो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आलावे कोई दूसरी सुविधा नहीं है ।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि दिन-भर और रात-भर हमारे चिकित्सक काम करते हैं, इनके मन के लायक नहीं करते होंगे, लेकिन उसकी ख्याति पर कोई प्रश्न-चिन्ह नहीं लगा सकता है ।

महोदय, आपने जो सुविधा दिया है तो जो हमारा आउट-पुट है वह रेकॉर्ड है । आप उनको देखिये कि उनकी परेशानियां क्या हैं । ट्रांसफर-पोस्टिंग में महोदय,....

[इस अवसर पर सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) ने आसन ग्रहण किया ।]

महोदय, हम मांग करेंगे कि जितने भी किरानी से लेकर आयुक्त से लेकर, डिप्टी सेक्रेट्री से लेकर मंत्री तक जितने लोग पंद्रह साल तक रहे हुए हैं, सबों के धन की जांच कराई जाए कि वे लोग कितना-कितना धन बनाये हैं ।

महोदय, एक, मेडी-केयर के बारे में हमने कहा है और दूसरा, जो हमने कहा है वह है विधायकों के लिए फंड की व्यवस्था जिससे वह इलाज करा सके । पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को हरेक डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा जाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को सब डिविजन अस्पताल से और पी०एच०सी० से जोड़ा जाए । उससे फायदा होगा कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जितने एक्सपीरिएन्स्ड डॉक्टर्स हैं, वे सप्ताह में, महीने में हर डिस्ट्रिक्ट में जाएं और अच्छे-से-अच्छा टेक्निक उसको उपलब्ध करावें और पी०एच०सी० से चार किलोमीटर, दस किलोमीटर पर मरीज जो हमारे आते हैं, वहां से पी०एच०सी० पर आ जाता है और इससे होगा कि हेल्थ का एक सिस्टम चलेगा । जापान में भी यही सिस्टम है । मेडिकल कॉलेज से सब सिस्टम जुड़े हुए हैं, इसलिए लेटेस्ट टेक्निक देने में वहां सुविधा होती है और हेल्थ का विकास होता है ।..... क्रमशः ...

डॉ० आर० आर० कनौजिया : ..क्रमशः... सरकार की जिम्मेदारी इतनी ही बनती है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जो पी०एच०सी० हैं, उन्हें इमरजेंसी के सामानों से परिपूर्ण कर दिया जाय ताकि सभी को समुचित इमरजेंसी का ईलाज करने की सुविधा मिल जाये । महोदय, तीन दिन पहले की घटना है । हमारे बरबीघा विधान सभा क्षेत्र में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से घायल को शेखपुरा ले जाया गया लेकिन वह रास्ते में ही मर गया । महोदय, इस तरह के एक नहीं, अनेको किस्से हैं । जितने भी सीरियस टाईप के मरीज होते हैं, लोकल कोई ईलाज का साधन उपलब्ध नहीं रहने के कारण वे लोग रास्ते में ही मर जाते हैं । महोदय, सबसे पहला प्रायरिटी का काम यह होगा कि जितने भी हेल्थ सब सेन्टर हैं, पी०एच०सी० हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उनको मजबूत किया जाय । साथ-ही, जो राशि दिया जाता है उसको भी मजबूत किया जाय ।

महोदय, मेडिकल कॉलेजों की शिकायत हमेशा होती रहती है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि टीचर्स का प्रमोशन उल्टा-सीधा मंत्रियों के चक्कर में होता है । महोदय, इसके लिए चाहेंगे कि एक एडवाइजरी कमिटी बनाया जाये और उसमें देश के प्रख्यात चिकित्सक रहें, पटना मेडिकल कॉलेज के हों या किसी भी मेडिकल कॉलेज के हों, उसके प्रिंसिपल रहें, चंडीगढ़ के हों, कहीं के हों । महोदय, डॉक्टर लोग कितना काम करते हैं, कितना रिसर्च किये हैं, कितना इमरजेंसी का ईलाज किये हैं, उनका हरेक छः-छः महीने में इवैल्युयेशन हो और वह एडवाइजरी कमिटी हर फैकल्टी का, ईलाज के हर डिपार्टमेंट के बारे में कमिटी अपना एक अद्यतन रिपोर्ट देगी, जिससे होगा यह कि किसी के प्रमोशन में बेईमानी नहीं की जा सकेगी, नीचे-ऊपर नहीं किया जा सकेगा । इसलिए महोदय, हरेक मेडिकल कॉलेज में इसके लिए एक एडवाइजरी कमिटी का गठन करा दिया जाये ।

महोदय, दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी नर्सिंग सेन्टर थे, जितने भी डिफ़िक्ट पड़े हुये थे, अभी थोड़े में पढ़ाई शुरू हुई है, पारा मेडिकल स्टाफ की पढ़ाई बहुत जरूरी है । अभी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थिति यह है कि वहाँ नियुक्ति नहीं होने के चलते एक स्वीपर से भी ओ०टी० एटेंडेंट का काम लिया जाता है । काम तो चल जाता है लेकिन क्वालिटी नहीं सुधरता है ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिए ।

डॉ० आर० आर० कनौजिया : महोदय, आज स्थिति यह हो गई है कि किसी को ऑपरेशन कराना है तो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, किसी को हर्निया का ईलाज कराना है तो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, किसी को कुछ भी ईलाज कराना है तो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल । महोदय, पटना में जितने भी अस्पताल हैं - राजवंशीनगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, पटना सिटी अस्पताल, उन अस्पतालों को भी मजबूत किया जाये । उन अस्पतालों में डॉक्टरों की पोस्टिंग कराकर वहाँ अच्छी ईलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जाये ताकि लोग वहाँ ईलाज के लिए जायें और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का लोड कुछ वहाँ जाये । महोदय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को एक रेफरल अस्पताल की तरह बनाया जाये ताकि उसमें एम्स की तरह सुपर-स्पेशलिटी आये ।

महोदय, विगत दिनों में एक आयुक्त का कमाल देखने को आया, सबकी बदली करके पैसे का मोचन का काम किया, अपना घर-द्वार बनाने का काम किया । इतना ही नहीं, महोदय, वैसा आयुक्त जो ऑलरेडी भूमि घोटेला में नामजद है, अपने कागज को दबवा लिया है और काम कर रहा है । महोदय, ऐसे लोगों की निश्चित रूप से जाँच होनी चाहिए ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिए, आपका २० मिनट हो गया ।

डॉ० आर० आर० कनौजिया : महोदय, दो मिनट और सुन लिया जाये, बहुत अच्छा-अच्छा सुझाव दे रहा हूँ, चांस बहुत कम मिलता है । महोदय, शिक्षकों का जो वेतनमान है, आपको शायद याद नहीं होगा, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतनमान लेकर प्रोफेसर का काम किया हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हुआ । आप बैठ जायें ।

माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय, अपना भाषण शुरू करें ।

श्री रामदेव राय : सभापति महोदय, माननीय जगदा बाबू के द्वारा प्रस्तावित कटौती प्रस्ताव के समर्थन में २-४ शब्द आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की सेवा में पेश करना चाहता हूँ ।

महोदय, मैं कोई बजट का ज्यादा ब्योरा नहीं जानता हूँ कि किस साल, किस आईटम पर कितना खर्चा हुआ ? मैं सिर्फ यह देखता हूँ कि गांवों में जो लोग रहते हैं, आज गांवों में रहने वाले लोगों की क्या दुर्दशा है, हम सभी जानते हैं । हुजूर, आप एक ओर बड़े-बड़े डाक्टर और डाक्टरनी जो प्रतिदिन सैंकड़ों मासूम बच्चों को गर्भ से आने के पूर्व ही मार दिये जाते हैं, आप उनको पुरुष्कृत करते हैं और दूसरी ओर आप गांवों के गलियों में, गांवों के झोपड़ी में, डगर-डगर पर गांव के वैसे बेरोजगार नौजवान जो गांवों में रहने वाले मासूम बच्चों की जिन्दगी बचाते हैं, आप उनको हाथ में हथकड़ी लगाकर जेल भेजने का काम करते हैं । इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आपको स्पष्ट करना होगा कि आप बी०पी०एल० की सूची वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा उपाय कर रहे हैं । मैं यह नहीं जानता कि उनके लिए कितना अनुदान भारत सरकार से आती है और कितना अनुदान बिहार सरकार देती है । मैं यह जानता हूँ कि बी०पी०एल० की सूची में रहने वाले लोगों के लिए प्राथमिक उपचार के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए आपने कौन सा कदम उठाया है । महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैंने पूर्व मंत्री जी का भी भाषण सुना और उनके उपलब्धियों का पिटारा यहां खुला और आगे वर्तमान मंत्री जी का भी भानुमति का पिटारा खुलने वाला है । उसमें से न जाने कितने जीव-जन्तु, कीड़े-मकौड़े कितनी उपलब्धियां उसमें से निकलेगी, मैं जानता नहीं हूँ । मैं सिर्फ यह जानता हूँ कि अगर हमारे माननीय मंत्री जी प्रोग्रेसिव हैं तो भारत की इतनी बड़ी आबादी जो पटना नहीं पहुंच सकती है तो आप वैसे लोगों के लिए ३ महीना में कौन सा कदम उठाया है । आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को बन्द कर रहे हैं, अतिरिक्त स्वास्थ्य उप केन्द्र को बन्द कर रहे हैं । जिला के अस्पताल में अगर आप शाम में जायेंगे तो वहां शमशान सा विरान रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं । जिला के गरीब लोग कहां जायेंगे, जिनके पास एम्बुलेंस के लिए पैसा नहीं है, वे कैसे आयेंगे पटना शहर में ?

हुजूर, आप कल स्वास्थ्य मेला लगाये थे, बहुत भीड़ वहां जुटी थी । क्या वहां पर कुछ पी०एम०सी०एच० वाले लोग अपना दर्द बता सकें । अगर नहीं बतायें तो अगर आप मरीज बनकर चलिए या शकुनी बाबू को बना दीजिए या मैं बन जाऊँ और फिर मेरी हालत देख लीजिए । अच्छा हो कि आप दोनों आदमी स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और मैं रोगी बनकर जाना चाहता हूँ । मैं आग्रह करता हूँ कि मेरी दुर्दशा को अगर आप देखेंगे तो कुछ देर के लिए चिन्ता जरूर कर लेंगे । लेकिन मेरी एटैन्डेन्ट की क्या हालात होगी, कहीं लात-जुत्ते नहीं खाने पड़ जायं, यह चिन्ता का विषय है । कल आप स्वास्थ्य मेले में थे, आपको कोई रोगी का एटैन्डेन्ट कहा कुछ, नहीं कहा होगा । चूँकि हमलोग लाव-लश्कर से भरे रहते हैं और कोई गरीब आपके पास नहीं जा सकता है । आप २५ रु० भोजन देते हैं , ३ रु० से बढ़ाकर २५ रु० शकुनी बाबू किये थे , अभी जैसा शकुनी बाबू ने कहा है । हम जानते हैं कि उनको कैसा केला खाने के लिए मिलता है । जो केला ८ दिन पहले सड़ गया है, वह केला उस गरीब को नसीब होता है, जो गरीब कभी केला का नाम भी नहीं लिया । माननीय मंत्री जी, पावरोटी की बात तो आप छोड़ दीजिए । दुध की बात तो छोड़ दीजिए, दुध कहां नसीब है । हम ही लोग दुध उत्पादक है, यहां ८ रु० किलो दुध मिलता है, जबकि पानी यहां १२ रु० लीटर मिलता है । उस गरीब को दुध कहां नसीब होगा, इस पर आप चिन्ता कीजिए । दवाई तो छोड़ दीजिए, आप उसके प्राथमिक उपचार के लिए क्या करते हैं ? आज गांव के सारे केन्द्र बन्द हैं, गांव में डाक्टर नहीं हैं, गांवों के अस्पताल में उपचार करने के लिए आप कोई सामग्री नहीं देते हैं । हुजूर, मेरे यहां मंसूरचक में एक सरकारी अस्पताल है । वहां आगे में थाना बैठता है और पीछे में कुत्ता भौंकता है । आप अपने जवाब में इसके बारे में बतायेंगे । मंसूरचक एक सरकारी अस्पताल है, २० वर्षों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अस्पताल था, वहां डाक्टर थे, दवाई थी, प्रबंध था, सारी व्यवस्था थी और अब सरकारीकरण के बाद

बिहार सरकार के वहां डाक्टर भी नहीं जाते हैं, वहां आपके डाक्टर के बदले कुत्ते भौंकते हैं । इस पर आपको सोचना होगा । आप मोबाईल सेंटर खोलने वाले हैं, आप मोबाईल होस्पिटल की व्यवस्था कर रहे थे । नहीं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप झोले छाप को ट्रेनिंग दीजिए, उसको रजिस्टर्ड कीजिए और उसको छूट दीजिए, वे अपने पैसे से ट्रेंड हो जायेंगे । वे गांवों के गरीबों को जान बचाते हैं, वे ५ रू० भी नहीं लेते हैं । गांव के गरीब बच्चों को सुई देकर, दवाई देकर, मरहम-पट्टी करके उसकी जिन्दगी बचाते हैं और उसको कलक्टर साहेब जेल भेजते हैं और जेल भेजकर वे अपना नाम कमा रहे हैं । आप दवाई भी नहीं देंगे, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी आप नहीं कर पाते हैं और जो उसके लिए तत्पर रहता है, गांव में सेवा दल बनकर तैयार रहता है । उसको आप जेल भेजीयेगा श्रीमान् जी तो आप प्रोग्रेसिव सरकार नहीं कहला सकते । .

(क्रमशः)

....क्रमशः...

श्री रामदेव राय : यह बात नहीं है, हम १५ वर्ष और तीन वर्ष की बात लड़ाई लड़कर प्रोग्रेसिभ नहीं हो सकते हैं । हम कौन-सा कदम उठाते हैं गाँव के गरीबों के लिए, यह देखना होगा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए । उतना नहीं देखना है हुजूर, आप एम०एल०ए० फ्लैट के अस्पताल को जरा शाम में निरीक्षण करके देखिए । क्या हालात हैं ? मैं १९७२ से एम०एल०ए० हूँ । मैं देखा हूँ उस अस्पताल को, आज भी मैं देखता हूँ, पट्टी खोलवाने के लिए मैं उस अस्पताल में जाता हूँ और डाक्टर साहेब के बदले कम्पाउंडर साहेब पट्टी खोलकर फेंक देते हैं और घाव उस जगह बह जाता है और कोई दवा भी नहीं मिलती है । जब एम०एल०ए० साहेब को दवा नहीं मिलती है तो गाँव में रहनेवाले जो गरीब लोग हैं, उनके इलाज की क्या व्यवस्था रहती होगी । गाँव के वो दर्द-बेदर्द बेचारे बिना इलाज के मरते चले जा रहे हैं और आप ११ अरब रूपया खर्च करके आज भानुमती का पिटारा हमारे सामने सदन में खोलेंगे श्रीमान् । लाल बत्ती जल गयी, पाँच मिनट ही समय मिलता है । मैं श्रीमान् से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप पहले गाँव की ओर चलें, जिसकी सारी आबादी गाँव में रहती है, वह पटना नहीं पहुँच सकता है । पी०एम०सी०एच० की हालात को, ठीक हमारे कनौजिया साहेब बोले कि यह बात ठीक है, वहाँ अच्छे डाक्टर हैं, उपचार भी आप कर देते हैं लेकिन कल होकर मरीज की क्या हालत होती है, उसको आपने कभी देखा है । मैं इसको बताता हूँ, एक श्री राम पोद्दार जी, बाबू भोला सिंह, बेगूसराय के विधायक के अनुशंसा पर, आपके माध्यम से पी०एम०सी०एच० में भर्ती हुए और परसों होकर अपना प्राण त्याग दिया, यह गरीब उपचार और दवाई के अभाव में । कोई देखनेवाला नहीं ? श्रीमान् मालिक ही इस देश को बचायेंगे, इस राज्य को बचायेंगे । अगर आप बचाने के लिए चले हैं तो जरा हमदर्द बनिए तो हमसबों का यह बिहार आपका कृतज्ञ रहेगा । मोवाइल सेंटर नहीं चलाकर, गाँव के सेंटर को आप मजबूत कीजिए । महोदय, दूसरी ओर आप देखियेगा कि गाँव में जितने भी दवा के दुकान हैं, वहाँ काले धंधे हो रहे हैं । पटना के पी०एम०सी०एच० के अगल-बगल के दुकान में जाली दवा बिकती है, क्या आपने कभी इसका जांच कराया है ? कभी जांच नहीं कराते हैं, हुजूर ? आपका ड्रग इन्स्पेक्टर क्या करता है ? हम नहीं बता सकते । गाँव में भी नकली दवा के धंधे होते हैं और श्रीमान् ऐसे धंधे को रोकने का इन्तजाम आप नहीं करेंगे तो आपका काम चलनेवाला नहीं है । अगर आप एलोपैथिक दवा नहीं दे सकते हैं तो आप आयुर्वेदिक दवा, जड़ी-बुटी की दवा, देशी चिकित्सा पद्धति को आप ठोस कीजिए । आज योगासन के लिए हमारी बिहार सरकार स्पेशल व्यवस्था करने जा रही है बाबू रामदेव दास जी के लिए ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : अब आप समाप्त कीजिए । माननीया सदस्या, श्रीमती रेणु देवी ।

श्री रामदेव राय : मगर रामदेव राय चिल्ला रहा है, इसकी बात भी तो जरा-सा सुनिए । आप जड़ी-बुटी दीजिए, अगर आपके पास हम योग में नहीं जा सकते हैं तो जड़ी-बुटी खिलाकर इलाज कीजिए । हमारे पुराने जमाने में, कैसे हमारे वैद्य हमारे प्राण की रक्षा करता था, आज आप इस बात से क्यों मुकर रहे हैं ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री रामदेव राय : मैं समाप्त कर दिया हूँ हुजूर, मैं पाँच मिनट के समय में कितना बोल सकता हूँ । देशी चिकित्सा पद्धति को, जड़ी-बुटी के माध्यम से, आयुर्वेदिक के माध्यम से गाँव के लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराइए श्रीमान्, स्वास्थ्य की रक्षा ही प्राणों की रक्षा हुई, वही भगवान की रक्षा होती है, आप तो सबके मालिक हैं तो जो सबसे बड़ा मालिक होता है या तो वह भगवान को पुकारता है कि भगवान मेरी रक्षा करो नहीं तो श्रीमान् की सेवा में डाक्टर साहेब के यहाँ गुहार लगाता है । उसके मालिक आप हैं और आपके रहते अगर दवा के अभाव में कोई गरीब प्राण त्याग कर देते हैं श्रीमान् तो आप कभी-भी सबसेसफल सरकार नहीं हो सकते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं चाहता हूँ कि आपलोग हमारे जगदा बाबू के कटौती प्रस्ताव को ही मान लेते तो बड़ी कृपा होती ।

श्रीमती रेणु देवी : सभापति महोदय, मैं आज स्वास्थ्य विभाग के बजट के मांग के पक्ष में बोलना चाहती हूँ । मैं बताना चाहती हूँ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री महोदय को कि आज पूर्व मंत्री महोदय ने कटौती-प्रस्ताव देकर जो अपना भाषण व्यक्त कर रहे थे तो मुझे कभी-कभी जो थोड़ी-बहुत समय मिली थी पाँच वर्षों में काम करने का, मुझे पीड़ा हो रही थी । जिस समय हमलोग कराह रहे थे इस जगह, तीन रुपये से दस रुपया करने के लिए ..

(व्यवधान)

इसलिए मैं बतलाना चाहती हूँ कि जो तीन रुपया था उस समय, हमलोगों ने इस बात के लिए आगाह किये तो इन्होंने दस रुपया किया और उस समय इसके लिए हमलोगों ने मंत्री जी को धन्यवाद भी दिया । लेकिन ये जो अपने पक्ष में कहना चाहते हैं कि मैं २५/- रुपया कर दिया हूँ तो २५ रुपया लागू क्यों नहीं हुआ ? आज जो हमारी सरकार की सोच है, वह चौतरफा सोच है ।

(क्रमशः)

श्रीमती रेणु देवी : क्रमशः, सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगी कि विगत १५ वर्षों में चाहे अनुमंडल अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो या बड़े-बड़े अस्पताल हों, आज वहां की हालत जर्जर है। विगत की सरकार ने कभी चिंता नहीं किया कि जो नौकरी कर रहे हैं, वे रिटायर होंगे और उसके बाद वह जगह खाली होगा, उसके बाद आनेवाले कौन होंगे। नर्सिंग ट्रेनिंग की जो शिक्षा पद्धति थी, नर्स ट्रेनिंग लेकर जाती थी, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया तो किसकी बात करते।

महोदय, मेडिकल कॉलेज की हालत के बारे में ६ महीना पहले पता लग गया था कि कैसे मेडिकल में बच्चे जाते हैं, उस समय मैं बार-बार उनसे आग्रह करती थी कि शकुनी चौधरी जी, बेतिया और गया का एक अपूर्वा अस्पताल है और ये वहां ऐसे सी०एम०ओ० और सुपरीटेंडेंट को देते थे, जो ४-५ महीने में रिटायर होनेवाले हों ताकि कोई भी काम न हो, किसी हास्पिटल में बिस्तर तक नहीं रहता था। लेकिन, हमारी सरकार की सोच है, इन्होंने सबसे पहले भवनहीन अस्पताल को भवन देने का प्रावधान पैसा देकर के किया है। ये कह रहे थे एम्स के बारे में, जिस बिहार में एम्स बने वहां की सरकार को संवेदनशील होना चाहिए था और हर हाल में जमीन उपलब्ध कराना चाहिए था, सरकार उसे बढ़ा सकती, लेकिन इन्होंने क्या किया इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा भाषण कर रहे थे कि यहां आइ०जी०आइ०एम०एस० को एम्स बनाना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज आइ०जी०आइ०एम०एस० का क्या हाल है। वहां पर ५०-५० मरीज एक वार्ड में हैं और दो नर्स काम करती है। वहां नर्स और डाक्टरों की कमी है और उस हिसाब से ५० मरीजों की देखभाल दो नर्स कैसे कर सकती है और ये कल्पना करते हैं कि उसे एम्स बनाना चाहिए। महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि निश्चित रूप से उसकी हालत बदलनी चाहिए।

महोदय, वे अपने भाषण के दौरान कह रहे थे कि हमारी सरकार में यक्ष्मा का सफाई कर दिया गया, लेकिन, मैं कहना चाहूँगी कि यक्ष्मा का जब माइक्रोस्कोप ही न हो, किसी का ब्लड टेस्ट देखा ही न गया हो तो यक्ष्मा को इन्होंने कैसे साफ कर दिया और ऐसे बहुत अस्पताल हैं। महोदय, हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रीजी ने ३८ जगहों का उल्लेख किया है, जहां नये सिरे से माइक्रोस्कोप लगाकर के यक्ष्मा को साफ किया जा सकता है। साथ ही जहां अन्य मशीनें लगाने की आवश्यकता है, वहां मशीन को लगाकर इसको समाप्त किया जा सकता है।

महोदय, आज ये कह रहे थे कि हमें बहुत बड़ी उपलब्धि कुष्ठ रोग, मलेरिया के उन्मूलन में मिली, लेकिन महोदय, मलेरिया उन्मूलन के लिए जो डी०डी०टी० छिड़काव होता है, वह गांव से लेकर शहर तक कहीं भी देखा जा सकता है, यह वर्ष २००० से ही बंद पड़ा था और यह इस वर्ष शुरू हो रहा है। महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने पारदर्शी तरह का कोई कार्ययोजना नहीं बनाया, लेकिन, हमारी सरकार की सोच है कि चाहे वह जिला में हो, चाहे इस प्रदेश के किसी भाग में हो, चाहे ग्रामीण इलाके में हो, जहां रेफरल अस्पताल और प्राइमरी सेंटर हो, वहां एक रोगी कल्याण कमिटी बनाना चाहिए और वहां की जो भी परेशानी हो, उसको रोगी कल्याण कमिटी में लायेंगे और उस कल्याण कमिटी से इसे प्रदेश कल्याण कमिटी को देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम राज्य में स्वास्थ्य को पहुंचा पायेंगे।

महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि जो पोलियो की क्रांति हुई है, यह ठीक है, यह पहले से आ रहा है, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगी कि अभी हाल में एक सप्ताह पहले सीतामढ़ी जा रही थी, पल्स-पोलिया के लोग झंडा लेकर, बैरियर लगाकर गाड़ी रोक रहे थे और एक बच्चा भी अगर गाड़ी के भीतर है तो उसको भी दवा पिलाना है। इस तरह से पल्स पोलियो का काम चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आनेवाले समय में जो सरकार की सोच है, वह बहुत कुछ करेगी।

आप कहते हैं कि वैक्सिन का भान हमारे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी ने गांव-गांव में भेजा है, यह हमारी सरकार की सोच है, इस तरह का भान जायेगा और दूर-दूर तक गांवों में, बच्चे जो यहां नहीं पहुंच पायेंगे उनको दवा देगा, उसको एक रोस्टर बनाकर के भेजा जायेगा, जहां बच्चों को हर तरह की दवा खसरा, टी०वी०, जो खानेवाले हर तरह के ड्राप्स उनके घर तक पहुंचाया जायेगा ये सोच इस सरकार की है। मैं कहना चाहूंगी कि आनेवाले दो-तीन महीने के भीतर आपके सामने आ जायेगा कि हमारी भान निकलेगी रोस्टर लेकर और गांव के गरीब के बच्चे जो हमेशा स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर हैं, उनकी जाँच करके उपयुक्त उसको दवा दे, इसकी व्यवस्था हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी की जो सोच है, मैं कहना चाहूंगी, उसमें एक स्पेशल बिन्दु के लिए आग्रह करूंगी मुख्यमंत्री महोदय से कि मंत्री महोदय, कैंसर एक बहुत ही भयावह रोग है और कैंसर से आपको मालूम होगा कि पूरे बिहार में १ लाख लोग पीड़ित हैं, जिसमें ५१ प्रतिशत महिलाएं हैं। जिसमें २९ प्रतिशत ब्रेस्ट कैंसर और ५१ प्रतिशत यूट्रस कैंसर से पीड़ित हैं। महोदय, ये बहुत ही भयावह बीमारी है और इसके प्रति लोगों की जागरूकता के लिए स्पेशल कार्यक्रम होना चाहिए, प्रत्येक अस्पताल में उन्हें जानकारी मिलनी चाहिए कि आनेवाले समय में यदि कैंसर को नहीं रोका जायेगा तो मरनेवालों की संख्या अभी ५० हजार है, शायद लाखों की तायदाद में पहुंच जाय। ये ऐसी बीमारी है जिसपर पहले रोक लग जाय तो उसका इलाज सस्ता और आसान हो जाता है। महोदय, यह बीमारी हमारे गरीब-गुरबे लोगों के भीतर जा रहा है, उसके लिए एक निमोटेस्ट होता है और इस मशीन को लगाने में २२ लाख रुपया लागत आता है, यह मशीन अगले बजट में प्रत्येक जिले के अस्पताल में देना चाहिए ताकि आनेवाले समय में हमारे यहां की महिलाएं जो ४० वर्ष से कम की हों, वे निश्चित रूप से यह टेस्ट कराके तैयार हो जाय कि मुझे क्या है, अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करेंगी। मैं कहना चाहूंगी कि आज जो हमारे पूरे एक्स-रे मशीन हैं, चाहे ब्लड टेस्ट के लिए जो मशीन हैं या जो अच्छे मशीन हैं, इन मशीनों को १९-१९ जिलों में बांटा गया है ताकि रोगी का उससे ब्लड टेस्ट कराया जायेगा, इतने कम समय में और इतनी बड़ी उपलब्धि इस सरकार की हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाय, वह कम ही होगी। मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ कि बिहार के विकास के लिए हमलोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, सब मिलकर के आगे बढ़ें, यही कह करके अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।

श्री रामदास राय: सभापति महोदय,

श्रीमती रेणु चौधरी: सभापति महोदय, मैं एक बात कहना भूल गयी थी। माननीय हमारे शकुनी चौधरी चाचा जी ने कहा है कि बहुत अच्छा काम किया है, तो एकजामपुल देना चाहती हूँ कि पूरे बिहार में एक ही प्लास्टिक सर्जरी डॉ० हैं, डॉ० एस०के० झा, जिनको उन्होंने १४ वर्षों तक नालन्दा मेडिकल कॉलेज, अस्पताल में रखा और जबकि आज पी०एम०सी०एच० में जगह खाली है। वहाँ भेजने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी।

श्री भोला सिंह: सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। यहाँ माननीय सदस्य के रूप में श्री शकुनी चौधरी हैं, यहाँ कोई चाचा और बाबा नहीं हैं, ये नहीं कहना चाहिए। वे माननीय सदस्य हैं, आपके चाचा आपके घर पर होंगे, यहाँ नहीं।

(व्यवधान)

श्री रामदास राय: सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, जो स्वास्थ्य विभाग की बिहार में स्थिति है, उसी के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बिहार की स्थिति आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में काफी दयनीय स्थिति होती जा रही है। इसके लिए व्यवस्था में कमी कहीं-न-कहीं है। हमारे राज्य में आबादी काफी बढ़ी है लेकिन आबादी के अनुपात में जो रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उसके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। आपको मालूम होगा महोदय, जो बजट पेश किया गया है, उसमें दर्शाया गया है कि स्वास्थ्य परिक्षेत्र में इस वर्ष योजना में २३६ करोड़ तथा गैर योजना मद में ९१४ करोड़ अर्थात् कुल १२४० करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। वर्ष २००४-०५ में इस परिक्षेत्र में ७८३ करोड़ रु० का ही प्रावधान था। ये बता रहे हैं, वित्तीय वर्ष २००४-०५ और २००५-०६ में किया गया था, इस बारे में नहीं बता करके यह बता रहे हैं कि वित्तीय वर्ष २००६-०७, ये भी बताना चाहिए। बीच में वर्ष २००५-०६ में क्या आपने खर्च किया? आपकी सरकार ने यहाँ खर्च किया, उसके बारे में बताना चाहिए ताकि देख रहे हैं कि इसको ७८३५ करोड़ रु० को हमने १२०० करोड़ कर दिया लेकिन बीच वाला छोड़ करके चकमा दिया है, ये लाना चाहिए था इसमें, इसलिए महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बिहार की स्थिति और फिर गाँव की स्थिति कितनी बदतर हुई है, स्वास्थ्य के मामले में जो आज हमारे माननीय सदस्य इस सदन में दर्शा रहे हैं और बोल रहे हैं। आज आपको इस पर विचार करने की जरूरत है। भारत सरकार ने आपको काफी रुपया दिया है। हम भारत सरकार को प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने ८२ अरब रुपया से अधिक आपको दिया है, काम करने के लिए। जिनकी आवश्यकता थी, आपके स्वास्थ्य के मामले में उतना आपने नहीं लिया है और बढ़ करके भी आपको रुपया लेना चाहिए ताकि गाँव तक पहुँचे। स्वास्थ्य के मामले में गाँव के अस्पताल है, ब्लॉक में अस्पताल हैं, अनुमंडल अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं। उनको मजबूत करने की जरूरत थी लेकिन आपने पैसा कम लिया है। इसलिए आप वहाँ ले जाइये गाँवों को मजबूत कीजिए, आपका पैसा है। महोदय, रोगी चलता है यहाँ से पटना के लिए रास्ते में कहीं गाँव, अनुमंडल, जिला में अच्छा डॉक्टर नहीं होता है इसलिए उनको वहाँ से आते-आते रास्ते में ही दम तोड़ना पड़ता है और चूंकि पी०एम०सी०एच० भी अस्पताल है यहाँ पर आते हैं तो न कहीं आधार मिलता है और जाते हैं पी०एम०सी०एच०। पी०एम०सी०एच० में कानून-व्यवस्था को भी देखिये। मैं गया था, मैं कई बार जाता हूँ। विधायक होने के नाते गया था, इस हालत में दलालों की यहाँ भरमार रहती है। आपके डॉक्टर आते हैं और घूम कर के चले जाते हैं।

श्री राम दास राय (क्रमशः): फिर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं । वहाँ दलाल कहते हैं कि हड़ताल है, डॉक्टर नहीं हैं प्राइवेट क्लिनिक में चले जाईये । बाध्य करते हैं पी०एम०सी०एच० में लोगों को कि आपको प्राइवेट क्लिनिक में जाना चाहिए । जब पूर्व में बिन्देश्वरी दूबे की यहाँ सरकार थी तो उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की बात की थी । आपकी भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए । प्राइवेट प्रैक्टिस जबतक खतम नहीं होगा, बंद नहीं होगा तबतक आपका काम, सरकारी काम सरकारी डॉक्टर से नहीं होगा । यह संभव नहीं है । प्राइवेट प्रैक्टिस पहले बंद कीजिये । इन डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल में भेजिये । हमें मालूम है गांवों में जो चिकित्सक होते हैं, ब्लौक में चिकित्सक होते हैं, वे शहर में रहना पसंद करते हैं । शहर में नर्सिंग होम खोलते हैं । शहरों में नर्सिंग होम की भरमार हो जाती है लेकिन जो गांव में ब्लौक में अस्पताल होता है वहाँ लोग आते हैं लेकिन वहाँ क्या होता है ? वहाँ न कोई पैथोलॉजिस्ट, न कोई डॉक्टर विशेषज्ञ ही रहते हैं । ब्लौक में महिला डॉक्टर है ? इसके बारे में आप चिन्ता नहीं करेंगे तो स्थिति सुधरने वाली नहीं है । एक्स-रे मशीन है जहाँ रेफरल अस्पताल है । वहाँ एक्स-रे मशीन है लेकिन उसके लिए आपका कोई विशेषज्ञ नहीं है और न कोई औपरेटर है, कोई चलाने वाला नहीं है । अब वहाँ जेनरेटर नहीं है और न उसके लिए डीजल है । इन सारी त्रुटियों पर आपको विचार करने की जरूरत है और यदि आपने विचार किया तो मैं समझता हूँ कि ९० फी सदी लोगों को राहत मिल जायेगी । जहाँ प्रखण्ड में अस्पताल है, अनुमण्डल में अस्पताल है और जिला में अस्पताल है उसमें लोग जायेंगे, उनको यहाँ नहीं आना पड़ेगा लेकिन इसके लिए डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की जरूरत है । पटना में आप देखते हैं बड़े बड़े नर्सिंग होम खुले हुए हैं । प्राइवेट लोग खोले हम उसके विरोध में नहीं हैं । लेकिन जो डॉक्टर सरकारी पैसा लेते हैं, महीना लेते हैं, कोई न कोई बड़े ओहदे पर रहते हैं यहाँ के अस्पतालों में और एन०एम०सी०एच० और पी०एम०सी०एच० और इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान हो या पी०एम०सी०एच० का हृदय रोग संस्थान हो इन सब को मजबूत करने की जरूरत है । किशन गंज से लोग चलते हैं और सिवान से लोग चलते हैं और रोहतास से लोग चलते हैं कि यहाँ अच्छा इलाज होगा लेकिन आते आते दम तोड़ देते हैं । आपको देखने की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि इससे बिहार के लोगों को राहत मिलेगी । बिहार के लोग दिल्ली जाते हैं एम्स में जाते हैं, एस्कोर्ट में जाते हैं और ये जाने वाले लोग चले जाते हैं हवाई जहाज से लेकिन जो गांव में रोगी होते हैं उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है किसी तरह से खटारा बस पर चलते हैं और रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं उनके लिए हर प्रखंड में एम्बुलेंस और उसके साथ ड्राइवर देते हुए सारी व्यवस्था करनी होगी और यदि वैसी हालत हो जाय रेफरल अस्पताल में और वहाँ से रोगी यहाँ आ जाय पी०एम०सी०एच में तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और उस व्यवस्था के लिए आप बजट में व्यवस्था कीजिये । यह बजट आपको मिला है १२ अरब रुपये से अधिक और इस पैसे से आप इन सारी बातों को देखिये । इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो शेखपुरा में है, उसमें आज भी त्रुटि है । आँख का इस्पताल बहुत अच्छा था लेकिन आज वहाँ क्यों गड़बड़ हो रहा है । औटोनोमस है । औटोनोमस में आपका अधिकार है क्योंकि आप पदेन चेयरमैन हैं यानी औटोनोमस होने के बावजूद आज देखिये वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर वहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं और दो तीन साल के बाद वे चले जाते हैं और उसका नतीजा होता है कि पद खाली हो जाता है । आज वहाँ बहुत से विभाग खाली हैं उसको देखने की जरूरत है और आज वहाँ हर विभाग में डॉक्टर नहीं

है । वहाँ पर रोगियों का इलाज नहीं हो सकेगा । मैं आपसे आग्रह करते रहता हूँ आप हमारे पुराने मित्र है और जानकार साथी हैं इसलिए आप इन बातों को देखिये और देखकर ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करने की जरूरत है । कहीं हम आपकी आलोचना करने के लिए नहीं आए हैं । आलोचना राजनीत में करते हैं करेंगे लेकिन बजट में जो व्यवस्था आपने की है हम चाहते हैं कि गांव के लोगों को ९० फी सदी हिस्सेदारी मिले क्योंकि गांव के रोगी आज कराह रहे हैं गांव के अस्पताल में कराह रहे हैं उनकी रक्षा कीजिये । यहाँ तो पैसे वाले लोग रहते हैं उनके लिए सारा विकल्प खुला रहता है लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए व्यवस्था कीजिये । यदि आपने व्यवस्था कर दी तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य के मामले में यह बिहार काफी मजबूत हो जायेगा । क्रमशः

श्री रामदास राय: क्रमशः....महिलाओं के लिए आगे बढ़कर रेणु जी बतला रही थी । रेणु जी बोल रही थी कि महिलाओं के लिए काफी परेशानी है । बात ठीक है कैंसर रोग होते हैं बड़े बड़े रोग होते हैं महिलाओं को । महिलाएं घरों में रहती हैं उनकी रक्षा नहीं हो पाती है, पेसा नहीं रहता है डा० कह देते हैं इतना ही दिन तक जिंदा रहना था क्या कहें । क्यों कहते हैं बात को क्योंकि साधन नहीं है उनके पास पटना तक, दिल्ली तक, मुंबई तक जाने का पैसा नहीं है इसलिए वे बात बोलते रहते हैं । इसलिए हमारी मांग है आपसे कि जो ५२९ ब्लॉक हैं आप देखेंगे बहुत ब्लॉक में आज भी अस्पताल नहीं है मुख्यालय में नहीं है । हमारे छपरा जिला के इसवापुर में आज तक अस्पताल नहीं है । कोई घटना हो जाती है तो लोग छपरा जाते हैं इलाज के लिए । मढ़ौरा अनुमंडल है अनुमंडलीय अस्पताल आज तक नहीं बना । ब्लड बैंक हर जिला में आप खोलिये सरकारी तौर पर ब्लड बैंक छपरा का आदमी आता है पटना से ब्लड ले जाता है, मोतीहारी से आदमी आता है ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री रामदास राय: मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन सारी बातों को ध्यान में रखिये रखकर के काम कीजिये ।

डा० सुनील कुमार: सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । अभी हमारे सभी सिनियर सदस्य स्वास्थ्य विभाग के बजट के कटौती के संबंध में बात कर रहे थे और साथ साथ बिहार के चरमरायी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था की भी चर्चा कर रहे थे । मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन यह बात सत्य है कि विगत कुछ सालों में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गयी थी । हमारी लोकप्रिय सरकार ने इन सारी बातों को ध्यान में रखकर समाज के पिछले पायदान में बैठे गरीब लोगों का ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग का बजट पेश किया है । स्वास्थ्य सेवा की चर्चा अगर करें तो विगत कई सालों में गरीबों को बेसिक स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही थी और छोटे छोटे रोगों के लिए पटना के प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता था, राज्य के बाहर जाना पड़ता था । इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है जिसमें सभी बेसिक स्वास्थ्य केन्द्र चाहे वह रेफरल अस्पताल हो, चाहे प्राइमरी अस्पताल हो चाहे जिला के अस्पताल हो सभी को उत्क्रमित और आधुनिक करने का प्रावधान है । हमारे रामदेव बाबू, दोनों रामदेव बाबू बहुत चिंता कर रहे थे कि गरीबों पर ध्यान नहीं दिया जाता है । अस्पताल में कुत्ते भौंकते हैं, बेड पर कुत्ते बैठे रहते हैं । रामदेव बाबू ने कहा हम ७२ से इस विधान सभा के सदस्य हैं । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि विगत १५ वर्षों में उन्होंने भाषण दिया ? क्या उस सरकार को गरीबों का दुख दर्द नहीं था । जो गरीब २० से ५० रुपया कमाते हैं उनके घरों के बच्चे बीमार पड़ते होंगे तो बिहार के किस अस्पताल में जाकर इलाज करायेंगे । कभी सोचा है । आज बजट की कटौती की बात करते हैं और स्वास्थ्य सेवा की बात करते हैं । मैं सरकार के समर्थन में कहना चाहता हूं कि हमारी लोकप्रिय सरकार ने इस तरह का बजट पेश किया है आज हमारे जितने महाविद्यालय हैं ६ महाविद्यालय और एक दंत महाविद्यालय सबके भवनों का जीर्णोद्धार निर्माण और उसमें आधुनिकतम मशीन लगाने का प्रावधान किया गया है ताकि जो बिहार राज्य के लोग बिहार से पलायन कर रहे थे अपनी स्वास्थ्य सेवा के लिए दिल्ली चंडीगढ़ और चेन्नई में घूल फांक रहे थे बिहार की वह जनता बिहार में स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सके । हमारी सरकार ने नीतिगत घोषणा किया है कि हम बिहार राज्य में ७ प्राइवेट मेडिकल कालेज बनायेंगे उसकी घोषणा के बारे में जरा सोचिये कि कहां सोच है । जहां हमारे बच्चे स्वास्थ्य शिक्षा पाने के लिए राज्य से बाहर जाते हैं करोड़ों करोड़ रुपया हमारे राज्य का दूसरे राज्यों में चला जाता है साथ साथ किसी भी मेडिकल कालेज के एफिलियेशन दिलाने के लिए मेडिकल काउंसिल में एफिलियेशन दिलाने के लिए ३०० बेड का आधुनिक अस्पताल होना चाहिए ।

क्रमशः

डा० सुनील कुमार : ...क्रमशः

आप सोचिये अगर ७ मेडिकल कालेज हमारे बिहार राज्य में खुल गया और ३००-३०० बेडेड आधुनिक अस्पताल खुल जायेगा तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आ जायेगी और बिहार राज्य के बाहर स्वास्थ्य सेवा के लिये नहीं जाना पड़ेगा, यह सोच है हमारी बिहार सरकार की ।

महोदय, अभी लोगों ने कहा कि छोटी छोटी सी जगह से गरीब मरीजों को रेफर करके ले जाने में दिक्कत है, लोगों ने कहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्द हो रहे हैं, हमारे २९८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उत्क्रमित करने का प्रावधान रखा गया है, इस बजट में राशि विमुक्त की गयी है, उन सभी में टेलीफोन की व्यवस्था की गयी है और सारी जगहों पर ऐम्बुलेंस देने की व्यवस्था की गयी है ताकि गरीब मरीज रेफर हों तो उनको सरकारी खर्च पर दूसरे अस्पतालों में ले जाया जा सके ।

महोदय, साथ ही साथ नेशनल लेवल की जो स्वास्थ्य सेवा है उसको उपलब्ध कराने के लिये सारी आधुनिक मशीन इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में लगायी जा रही हैं ताकि नेशनल लेवल की स्वास्थ्य सेवा यहां की जनता को दी जा सके । आप सभी जानते हैं और लोगों के भीतर भी है कि ७० प्रतिशत आबादी बिहार की गांव में रहती है और उन गांवों की आबादी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है । ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का उद्देश्य जानलेवा बीमारियों को रोकने के लिये हमारी सरकार ने एक अभियान चलाया है, उसकी पूर्ति के लिये ८०० भान का प्रावधान किया गया है ।

सभापति(श्री हरि नारायण सिंह) : दो मिनट में समाप्त करें ।

डा० सुनील कुमार : पांच मिनट महोदय । ८०० भान की व्यवस्था की गयी है जो पूरी तरह से स्वास्थ्य जागरूकता लेकर और लोगों में इम्युनाइजेशन करे ।

महोदय, दूसरा, जननी सुरक्षा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति महिलाओं को जननी के लिये ७०० और शहर में ६०० रुपये देने का प्रावधान किया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक हजार की आबादी पर आशा का चयन किया गया है, जो २००५-०६ का २९७२७ में २९९७८ का चयन हो चुका है, ऐसे ग्राम स्तर पर चयनित एक साक्षर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगी जो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में किस तरह की सहायता प्रदान करेगी, विगत कई वर्षों से देखा गया था कि सरकार दवा के लिये भी राशि उपलब्ध कराती थी लेकिन उसका क्रय नहीं होता था, सारी राशि अभी कलेक्टर के यहां पड़ी हुई है, उनके भेदभावपूर्ण रवैया, टालू रवैये के कारण लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है, हमारी सरकार ने एक क्रय नीति बनायी है जिससे टेंडर निकाल कर अच्छी अच्छी कम्पनियों से दवाईयों का रेट फिक्स करायेंगे और जिले में अगर आवश्यकता पड़े तो जिलों के लिये उस रेट पर दवा का क्रय कर सके ।

सभापति(श्री हरि नारायण सिंह): डाक्टर साहब, अब आप समाप्त करें । एक मिनट में समाप्त करें ।

डा० सुनील कुमार : साथ ही मैं अपनी सरकार को भी सुझाव देना चाहता हूं । पांच मिनट दिया जाय ।

सभापति(श्री हरि नारायण सिंह): एक मिनट ।

डा० सुनील कुमार : मैंने अपना इंट्रोडक्शन यह नहीं दिया है कि मैं डाक्टर हूं । मैं बी०पी०एस०सी० से मेडिकल आफिसर था, उससे रिजाइन करके मैं आपके बीच में आया हूं ।

....क्रमशः

S/o. (उ-1/10/9/11) - (क्रमशः):- सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिकायत है कि डाक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं तो सरकार से मेरा आग्रह है कि जहाँ प्राईमरी हेल्थ सेंटर बनाते हैं, वहाँ पर सरकार डाक्टरों के रहने की व्यवस्था करें और वहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें। कभी अपने छाती पर हाथ रखकर देखें कि अगर आपको सुदूर देहात में आपको नौकरी करने के लिए भेजा जायेगा, जहाँ पर रहने के लिए आपको घर न मिले, पीने के लिए पानी न मिले, तो क्या आप जायेंगे? मेडिकल ट्रीटमेंट दो पार्ट में बँटा हुआ है, एक प्रीभेनटिव एक क्यूरेटिव। प्रीभेनटिव का मतलब है अगर आप स्वच्छ जल उपलब्ध करायेंगे तो न आपको डायरिया होगा, न डिसेंटरी होगा, न जानडिसहोगा, न हेपेटाइटिस ए होगा और न हेपेटाइटिस बी होगा।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह):- अब आप समाप्त कीजिये। माननीय सदस्य श्री दुलारचन्द सिंह जी।

S/o. (उ-1/10/9/11) - महोदय, एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। मैं सरकार से यह भी मांग करता हूँ कि एक अंधापन जो बिमारी है, जिसको कैटेरेक्ट कहते हैं, इससे सभी को प्रभावित होना है उसका एडवांसमेंट पूरे हिन्दुस्तान में हुआ है लेकिन फेको सर्जरी हमारी सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, अभी माननीय सदस्या श्रीमती रेणु देवी ने कहा कि कैटेरेक्ट से महिलाएँ आज त्रस्त हो रही हैं।
(व्यवधान)

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह):- अब आप समाप्त करें, आप बैठ जाइये, आपका समय हो गया पूरा। माननीय सदस्य श्री दुलारचन्द सिंह जी। आप सात मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे।

श्री दुलारचन्द सिंह:- सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट पर एवं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष की तरफ से स्वास्थ्य के संबंध में चर्चाएँ चल रही हैं। आज देश ही नहीं बल्कि परदेश भी गाँवों का देश है। अधिकांश जनता गाँवों में, देहात में रहती है। शहरों में बड़े-बड़े अस्पताल, बड़े-बड़े नर्सिंग होम चल रहे हैं, लेकिन जो देहात के लोग हैं, उनको कितना कठिनाई होता है, उनको कितना कष्ट होता है, इसपर भी सदन में विचार होना चाहिए। सभापति महोदय, आप चले जाइये देहात में, जिस अनुपात में बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में हॉस्पिटल, सेंटर, सब-सेंटर खुल नहीं पा रहे हैं और जहाँ खुले हुए भी हैं, वहाँ इनके डाक्टर पदस्थापित नहीं हैं और इसका नतीजा यह है कि वह अस्पताल, सेंटर या सब-सेंटर मात्र कंपाउन्डर के भरोसे चल रहा है, इस बात को सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि अधिकांश लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, वह उनको मुहैया नहीं करा पा रही है, निश्चित तौर पर केवल यहाँ पर भाषण देने से काम नहीं चलेगा, चाहे किसी की भी सरकार हो, सत्ता पक्ष के द्वारा बार-बार यह आरोप लगाया जाता है कि १५ वर्षों तक किसकी सरकार थी, अरे भाई १५ वर्षों तक तो इनकी सरकार थी, अगर ये बढ़िया काम किये होते, तब ये यहाँ पर नहीं न आते, लेकिन अब तो ये इधर आ गये, वहाँ पर तो अब आप आप गये हैं, अब तो आपको बढ़िया-बढ़िया काम करना चाहिए। मैं तो सभापति महोदय कहना चाहूंगा कि एक स्वस्थ परम्परा होनी चाहिए। अगर विपक्ष के लोगों के द्वारा अच्छी बात कही जाती हो, तो उसे सरकार को धैर्य से सुनना चाहिए, यह सरकार की जिम्मेवारी है कि जनता को सुविधा अधिक से अधिक हम कैसे दे सकते हैं, इसपर ध्यान देना चाहिए, केवल आरोप प्रत्यारोप करके इस सदन का बहुमूल्य समय को नाहक बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। इसलिए सभापति महोदय, मैं साफ-साफ माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूँ कि बिहार की जनसंख्या अन्य राज्य के अनुपात में काफी बढ़ रही है। जैसे बिहार की जनसंख्या ग्रामीण स्तर पर २८.३ है तो शहरी स्तर पर २९.३ है, उसीतरह से झारखंड में ग्रामीण स्तर पर २१.६ है, तो शहरी स्तर पर २९ प्रतिशत है, उसीतरह से उत्तरांचल का ग्रामीण स्तर १५.२ प्रतिशत है, तो शहरी क्षेत्र ३२.८ है, उसीतरह से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र १४.२ प्रतिशत है, तो शहरी क्षेत्र ३६.२ है, उसीतरह से

पंजाब में ग्रामीण क्षेत्र में १२.३ है तो शहरी क्षेत्र में ३७.६ के रेशियो में यह जो बढ़ रही है तो अन्य जगहों में जनता की सुख-सुविधा के लिए सरकार जो धन मुहैया करा रही है, सेंटर सब सेंटर खोल रही है, लेकिन जनसंख्या जिस अनुपात में वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में बिहार में सेंटर, सब-सेंटर नहीं खुल रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या देहात के लोगों को भी सुख-सुविधा उपलब्ध करायेंगे? क्योंकि ये आँकड़े भी बताते हैं।

क्रमशः

श्री दुलार चंद सिंह :क्रमशः माननीय दूबे जी तत्कालीन मुख्य मंत्री थे, तो डाक्टरों के प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश जारी किया था । कानून बना था लेकिन आज भी डाक्टर लोग प्राईवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं । प्राईवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए आप इच्छा शक्ति रखते हैं या नहीं ? बड़े - बड़े जो लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं , वे तो नर्सिंग होम में जाकर अपना ऑपरेशन करवा लेते हैं लेकिन सरकार सिर्फ गरीबों की बात करती है, गरीब शब्द अब ऐसा लगता है, कि वह तार-तार हो गया है। सारे लोग इस शब्द के माध्यम से बालते हैं कि गरीबों के लिए यह करेंगे, वह करेंगे । आज मैं पी०एम० सी०एच० गया हुआ था । नवीनगर में हुए एकसीडेंट में ८ लोग वहां मरीज के रूप में भर्ती थे लेकिन उनका ऑपरेशन नहीं हो सका है । मैं सभापति जी बतलाना चाहता हूँ कि एक मरीज पर ४.७५ रुपये एक मरीज की दवा पर खर्च किये जाते हैं, ४.७५ रुपया से एक दिन में एक मरीज को कौन सी दवा मिलेगी, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए ऐसे गरीब लोगों को दवा दीजिये । जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वे इंग्लैंड अमेरिका जाकर ऑपरेशन करा लेते हैं । अस्पताल में जो गरीब लोग हैं, उनकी दवा के लिए सुविधा उपलब्ध कराइये । सभापति महोदय, जितने भी जिले अस्पताल हैं, कहीं भी दांत के डाक्टर नहीं हैं । वहां दांत का स्पेशलिस्ट हो । सभापति जी हम कहना चाहते हैं कि देहात के जितने अस्पताल हैं, जिला स्तर के जो अस्पताल हैं, वहां पर दांत के डाक्टर की व्यवस्था सरकार करे । महोदय, कालाजार से अनेक लोग मर रहे हैं लेकिन डी०डी० टी० का छिड़काव नहीं हो रहा है । सरकार के द्वारा छिड़काव का कार्य कराया जाना चाहिए । डी०डी०टी० का छिड़काव कहां हो रहा है ? आज विधायक फैल्ट में तो दवा का छिड़काव नहीं हो रहा है तो देहात में क्या होगा । इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि छिड़काव होनी चाहिए सरकार इस पर क्या कार्य कर रही है? छिड़काव होनी चाहिए । ४६ प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं । शहर की केवल बात नहीं होनी चाहिए , गांव की बात होनी चाहिए । जन समस्याओं के बारे में बात होनी चाहिए । केवल गरीब के नाम लेकर गरीब शब्द को अपमानित करने की बात नहीं होनी चाहिए । गरीबों के उत्थान के लिए ठोस कानून बनना चाहिए, इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए । आज स्थिति है कि दवा के अभाव में गरीब लोग मर जाते हैं ।

श्री नन्द कुमार नन्दा :सभापति महोदय, बिहार में स्वास्थ्य की जो हालत है, वह बहुत जर्जर है। यहां प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। १०-१० कि० मी० तक लोगों को अस्पताल के लिए पैदल जाना पड़ता है और अस्पताल से डाक्टर गायब हैं , कहीं डाक्टर नहीं हैं । लोगों को भूत प्रेत ओझा, गुणी के चक्कर में रहना पड़ता है। यहां बिहार में ४२ रुपया प्रति व्यक्ति खर्च हो रहे हैं जबकि दिल्ली में १९८ रुपया, यहां तीन हजार पर एक बेड है जबकि अन्य राज्यों में कम ही मरीज पर बेड है । एम्स का उद्घाटन बहुत जोर शोर से हुआ लेकिन निर्माण कार्य नहीं चल रहा है । यहां पर नकली दवाओं का भरमार है । आज अखबार में देखा है कि भ्रूण हत्या चल रहा है , यह क्यों चल रहा है ? सरकार की व्यवस्था है इसको चेक करने की या नहीं । यहां स्वास्थ्य केन्द्र में केन्द्र सरकार के करोड़ों रुपया हैं जो सरंडर हो जाते हैं तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि अस्पतालों की संख्या बढ़ायी जाये जन संख्या के अनुपात में । यहां जो भी भ्रष्ट डाक्टर हैं या कोई भी अधिकारी जो अनियमितता में संलग्न हैं या अमानवीय कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये और स्वास्थ्यकर्मी जिन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, उन्हें भी समय पर वेतन उपलब्ध कराये जायें और बजट में इस संबंध में रकम बढ़ायी जाये ।

टर्न-36/सत्येन्द्र/9-3-06

श्री व्यास देव प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो सदन में बजट प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, विगत पन्द्रह वर्षों से जो यहां कुशासन की सरकार चल रही थी उसके चलते विकास के जितने भी स्ट्रक्चर है वो सारा स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है। जिस तरह से हमारे यहां स्कूल और कॉलेज में शिक्षकों का अभाव है, कार्यालय में कर्मचारियों का अभाव है, अफसरों का अभाव है उसी तरह से मेडिकल क्षेत्र में भी डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों का अभाव है। सभापति महोदय, वर्तमान में एन.डी.ए. की सरकार आयी है, यह सरकार इसे महसूस कर चुकी है कि यहां स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूप से चरमरा गयी है, उसकी आधारभूत संरचना भी विगत पन्द्रह वर्षों में समाप्त हो चुकी है उसको ठीक करने के लिए यह सरकार तत्पर है, इसके लिए हमारी सरकार ने फैसला ले लिया है। महोदय, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह बात सदन में उठाया कि यहां ऐम्स का शिलान्यास किया गया था लेकिन आज तक उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं करायी गयी जिसके कारण इसकी सुविधा बिहार के लोग नहीं ले पा रहे हैं। महोदय, हमारी जो सरकार है, उसके जो मंत्री हैं, चन्द्रमोहन राय जी, वे इस ऐम्स के निर्माण में, जो भी अड़चने आ रही हैं, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व की सरकार में इस हेतु मात्र 72 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी गयी थी। वर्तमान सरकार और 28 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है। मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूँ कि जो सरकार तीन माह से ही है, उसके कार्यकलाप पर वाद-विवाद खड़ा किया जा रहा है। महोदय, हम पूछना चाहते हैं पूर्व की सरकार द्वारा गरीबों के लिए कौन सा काम किया गया जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, इन पन्द्रह वर्षों में जो पूर्व की व्यवस्था थी उसको भी उन्होंने समाप्त करने का काम किया है और वो तीन महीने में ही किस नैतिकता के आधार पर कहते हैं कि सम्पूर्ण सुधार हो जाय। वर्तमान सरकार ने जनता के समक्ष वादा किया है कि 500 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जायेगी, पांच हजार की आवादी पर एक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जायेगी इसके लिए सरकार अलग से पैसा की व्यवस्था बजट में किया है। अस्पतालों को आधुनिकीकरण करने के लिए यह सरकार प्रयास कर रही है, जितने भी अस्पताल हैं उन सारे अस्पतालों को आधुनिकीकरण करने के लिए योजना बनायी जा रही है। सभापति महोदय, मैं बतलाना चाहता हूँ हमारे यहां जो पांच मेडिकल कॉलेज हैं, उन मेडिकल कॉलेजों की स्थिति कितनी दयनीय हो गयी है, यह आप जानते हैं, इसमें सुधार हेतु हमारी सरकार ने 16 करोड़ रुपया का आवंटन दिया है जिससे मशीन की खरीद की जायेगी। अस्पतालों के भवन जो जीर्णोद्धार है इसके लिए राशि दी जा रही है। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार पटना में एक अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। (कमशः)

श्री व्यासदेव प्रसाद : क्रमशः इस तीन महीने की अवधि में वर्तमान सरकार ने अपोलो के एक ब्रांच को यहां खुलवाया है और साथ-ही-साथ, जो यहां का महावीर कैंसर हॉस्पिटल था उसमें जच्चे-बच्चे के लिए हॉस्पिटल पूरे बिहार में उपलब्ध नहीं था । कहा जाए कि पूरे नॉर्थ जोन में इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी । हमारे वर्तमान सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और आज इस बिहार में कार्यरत होने जा रहा है ।

महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने जो वायदा किया है, यहां पर २८०० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जा रही है और उसके निर्माण के लिए वर्तमान सरकार रूपए भी मुहैया करने जा रही है और मैं समझता हूं कि उसके लिए इनके द्वारा पहले ही पैसे भेज दिए गए हैं उनके निर्माण के लिए और एक साल के अंदर १६००० उपकेन्द्रों का, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का इनके द्वारा निर्माण कराने की योजना है ।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में इस प्रदेश में योजना मद में ३२६ करोड़ तथा गैर-योजना मद में ९१४ करोड़ का प्रावधान करके १२४० करोड़ रुपये का प्रावधान इस सरकार ने किया है जब कि विगत सरकार जो मात्र ७८३ करोड़ रुपये का प्रावधान उसमें किया था । गैर-योजना मद में, आपके माध्यम से सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए इस वर्तमान सरकार ने २० करोड़ रूपए का प्रावधान किया है और प्रमण्डलीय अस्पतालों के भवन निर्माण के लिए २५ करोड़ रूपए का प्रावधान किया है तथा सदर अस्पताल भवन निर्माण के लिए ३३ करोड़ रूपए का प्रावधान इस वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया है तथा दवा और अस्पतालों के जीर्णोद्धार और उसकी मरम्मत के लिए २८१ करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में निजी क्षेत्रों को भी बढ़ावा देने का काम प्रारम्भ किया है । उसके द्वारा उसको प्रोत्साहित करने का भी काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है और साथ-ही-साथ जो इसके तहत इनको पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सुविधाओं तथा इसके रख-रखाव के लिए इसकी व्यवस्था की जा रही है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि वर्तमान में जो सरकार है, कहा गया है - " होनहार बिरवान के होत चिकने पात ", वैसी ही स्थिति वर्तमान सरकार की है और आने वाले समय में, मैं समझता हूं कि बिहार की गरीब जनता के लिए जो सुविधा पहले से उपलब्ध नहीं है, वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में यह सरकार सक्षम होगी । जयहिन्द, जय भारत ।

श्री लाल बाबू राय : माननीय सभापति जी, आज सदन में स्वास्थ्य विभाग पर लाये गये प्रस्ताव पर जो बहस चल रही है, इसपर वरिष्ठ माननीय सदस्य, जगदा बाबू, अच्युता बाबू, रामदेव राय जी और राम दास राय जी द्वारा जो कटौती-प्रस्ताव लाया गया है, उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, उसी संदर्भ में मैं अपना विचार देने के लिए खड़ा हूँ ।

महोदय, जहाँ तक माननीय वरिष्ठ सदस्यों ने अपना विचार रखते हुए बहुत सी बुनियादी चीजों को बताया है, मैं इस विभाग के विषय में जहाँ तक जानता हूँ, उसके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार के माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हुये हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भी सुविधाएँ आपके द्वारा अस्पतालों में जा रही हैं, चाहे वह गैर योजना मद की राशि हो या योजना मद की राशि हो, उन पर जबतक आपकी पैनी निगाह नहीं रहेगी तबतक उसके बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं और हमलोग देखते हैं कि चाहे वह दवा खरीदगी का मामला हो, भवन निर्माण का मामला हो, पदाधिकारियों के द्वारा जो भी लापरवाहियाँ होती हैं, जब आप इसके लिए अरबों रुपये खर्च करते हैं, उस खर्च का कहाँ सदुपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस संदर्भ में हमलोग कटौती-प्रस्ताव लाकर आपको अपने विचारों से अवगत कराना चाहते हैं ।

महोदय, इस संदर्भ में जहाँ तक अस्पतालों में हमलोग देहात में जाते हैं, जो आपके पी०एच०सी० हैं, एडीशनल पी०एच०सी० हैं या जो जिला के अस्पताल हैं, सदर अस्पताल हैं, वहाँ की व्यवस्था को हमलोग देखते हैं या राजधानी के अस्पतालों में जब हमलोग क्षेत्र के रोगियों को लेकर ईलाज के लिए यहाँ आते हैं तो हमलोग देखे हैं, जो स्थिति दिखाई पड़ती है वह बहुत भयानक दिखाई पड़ती है । इतना अरबों रुपये खर्च करने के बाद यह स्थिति है । वहीं अगर आप दूसरे प्रदेश के अस्पतालों में चले जायें, हमें भी दूसरे प्रदेश के अस्पतालों में जाने का मौका मिला है, मालूम पड़ता है कि कोई स्वर्ग की जगह हो लेकिन वहीं दूसरी ओर अपने राज्य के अस्पतालों में यदि आप जायें, रोगी के साथ जो अच्छा व्यक्ति जाता है, दो दिनों के बाद वह भी रोगी बन जाता है, ऐसा माहौल आपके यहाँ अस्पतालों में दिखाई पड़ता है । इसीलिए हमलोग कटौती प्रस्ताव लाये हैं कि आपको बुनियादी चीजों से अवगत करायें कि आज जो खर्च करने जा रहे हैं, उसपर यदि आप पैनी निगाह नहीं रखेंगे तो अरबों नहीं, खरबों रुपये खर्च करके भी बिहार की कोई भलाई नहीं होने जा रही है ।

माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हुये हैं, योग्य हैं और इनकी योग्यता पर हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी देखरेख में बिहार जैसे गरीब प्रदेश के गरीबों को आपके विभाग से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं या जो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनकी जो अभी व्यवस्था है उसमें आप सुधार करेंगे ।

महोदय, ऑपरेशन थियेटर की जहाँ तक बात है, कई बार देखने का मौका मिला है, वहाँ इतनी दुर्गंध रहती है कि रोगी वहाँ जिस चीज के ईलाज के लिए जाता है, वह ठीक होगा या नहीं होगा, बहुत सारी दूसरी बीमारियाँ हो जाती हैं, ऑपरेशन के समय उसको दूसरी बीमारी भी पकड़ लेती है । महोदय, ऑपरेशन थियेटर की राफाई से लेकर कोई इंतजाम की व्यवस्था वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है । चाहे पी०एम०सी०एच० हो या और जो भी बड़े-बड़े अस्पताल आपके हैं, कोई सुविधा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है । इसके लिए आप क्या सोच बनाये हैं, उसके बारे में कोई प्रतिवेदन आपकी तरफ से हमलोगों को अभी तक नहीं मिला है लेकिन हमको लगता है कि आगे आप हमलोगों को इससे अवगत करायेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं । तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है, अस्पतालों की व्यवस्था सही हो और वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त हो, यही मैं माँग करता हूँ ।

महोदय, आपका जो डायग्नोस्टिक सेन्टर है, वे सही नहीं हैं । लोगों को बाहर से काम कराना पड़ता है जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है । आपके विभाग की तरफ से कर्मचारी उपलब्ध हैं, अगर सरकार सुविधा दे रही है लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं मिले तो यह जो पैसा गैर योजना मद का कर्मचारियों के वेतन में खर्च करते हैं उसका कोई उपयोग नहीं है, उनको सुख-सुविधा आप देते हैं, उनके बाल-बच्चे अच्छे ढंग से रहते हैं तो गरीबों के बच्चों को भी सुविधा उपलब्ध करायें । इसमें माननीय मंत्री जी आपको ध्यान देने की जरूरत है । हमलोग तो आपको सुझाव देते रहेंगे, सदन में हो या और जहाँ कहीं भी आपके पास जाकर सुझाव दें ।

सभापति महोदय, कुष्ठ निवारण के बारे में कुछ वरिष्ठ माननीय सदस्य उठा रहे थे, इसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है । जो भी डॉक्टर हैं वे अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं रहते हैं । दो-दो प्रखंड पर एक सेन्टर है, हमलोगों के यहाँ भी है, जो काफी दूर-दराज के इलाके हैं वहाँ भी सेन्टर बनाया जाये । जो सेन्टर हैं, वे भी सक्रिय नहीं हैं और जो डॉक्टर हैं वे मनमानी करते हैं । इसपर भी आप अपने स्तर से ऐक्शन लेंगे, यह मैं उम्मीद करता हूँ ।

..क्रमशः...

श्री लाल बाबू राय : (क्रमशः) जो नर्सिंग होम चलते हैं, जो आपके अन्दर में हैं । नर्सिंग होम की स्थिति यह है कि अगर कोई गरीब इलाज कराने के लिए चला जाय तो बिना गहना-गुड़िया या खेत बेचे हुए बिना उसका गुन्जाईश होने वाला नहीं है, जो आपके ही कंट्रोलिंग में आता है, यह आपके ही विभाग से संबंध है । इस पर आप कैसे कंट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े लोग खोलकर बैठे हैं और वहां २-४ गुन्डों और रंगबाजों को रख करके वे गरीबों का शोषण करते हैं, जब वे गरीब इलाज कराने के लिए जाता है और रोगी को बन्द कर देता है और कहता है कि जाओ तुम पैसा लाओ, तब टांका काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे । इस पर आप सोचिए, जहां लगना चाहिए २ हजार रु०, वहां १२ हजार रु० मांगता है । रोगी भागे-भागे जाता है, हमलोगों को पकड़ता है, कुछ हमलोग इन्तजाम करके देते हैं, कुछ कर्जा लेता है, फिर खेत बेचता है, तब जाकर उसका इलाज होता है, इस पर भी आपको सोचना चाहिए और इस पर आपको कंट्रोल करना होगा । ये जो नर्सिंग होम के नाम से जाने जाते हैं, ये समझिए कि पॉकेट काटने का सेंटर बनाये गये हैं, इस पर आपको कंट्रोल करना होगा । छपरा में तो स्थिति बहुत विकराल है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा और पटना की स्थिति तो आप जानते ही होंगे ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

श्री लाल बाबू राय : हुजूर, आपकी जो दवा कम्पनियां जो दवा सप्लाई करती है, उनमें गुणात्मक अभाव देखा जाता है । उसमें न जाने किस टाईप से आप क्या व्यवस्था रखते हैं । विभाग के तरफ से जो कम्पनियां आपके सप्लाई के लिए दवा बनाती है, उसका प्रोटेंसी अलग होता है और वही कम्पनी जो दवा सप्लाई करती है, उसका मार्केट में अलग प्रोटेंसी होता है । जो मरीज दवा खाता है, उसमें कोई भलाई नहीं होती है, रोगी कहता है कि ठीक नहीं हुआ । इसलिए आप पर से विश्वास उठता है और कहता है कि होस्पिटल के दवा से कुछ नहीं होता है । इसलिए रोगी फिर प्राइवेट दवा खरीदता है । इसलिए आप जो भी दवाईयां दे रहे हैं, उसमें गुणात्मक सुधार की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ । इसके साथ ही हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री रामदेव बाबू कह रहे थे, पी०एम०सी०एच० के गेट पर नकली दवा की उपलब्धता की बात, यह बिल्कुल सत्य है । मैं कई रोगियों के साथ गया हूँ, जब उन रोगियों का इलाज चल रहा था और दवा काम नहीं कर रहा था, रोगी बार-बार फोन किया, हमलोग गये और पाये कि यह दवा नकली है । इसलिए इसपर आप कैसे कंट्रोलिंग करेंगे, इसपर आप सोचेंगे माननीय मंत्री महोदय, मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ । जयहिन्द ।

श्री राजू कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग की मांग पर सरकार के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में कुछ बोलने जा रहा हूँ । खासकर के सभापति जी, पूर्व में सारे माननीय सदस्यगण बता रहे थे कि इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष दोनों में बातचीत चल रही थी । मैं सरकार के पक्ष में अपनी बात रखना चाहता हूँ ।

सभापति महोदय, खासकर के सदन में मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है, इसलिए हम सबलोगों से, खासकर के सारे माननीय सदस्यों से, सभापति महोदय से कहना चाहूंगा कि कुछ त्रुटि भी हो तो मुझे सिखाने का काम करेंगे ।

खासकर के प्रस्ताव के बारे में वर्तमान सरकार की जो नीति रही है, जिसको मैंने पढ़ा है और उसको अच्छे ढंग से अध्ययन किया है । पूर्व में जो क्रिया-कलाप चल रहा था विगत १५ वर्षों में, उसके बारे में कहा जाय कि इन १५ सालों में क्या हुआ है ? हमारे बिहार में, बिहार के अन्दर खास करके वहां पर जहां दूर-दूर में सुदूर गांव बसते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है ? उस व्यवस्था पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा । मैं खासकर के पिछले १५ सालों में, खासकर के १८ सालों से मैं विकसित देश में रहा हूँ और वहां भी देखने का मौका मिला था, वहां पर किस प्रकार का स्वास्थ्य व्यवस्था था । १९८० के आसपास हिन्दुस्तान के अन्दर बिहार में मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ और यहां भी मुझे देखने का मौका मिला था लेकिन इन १५ सालों में यहां कैसी व्यवस्था हो गई ? किसी भी प्रखंड

मुख्यालय में कहीं न कहीं किसी स्तर पर दवा का वितरण होता था, स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर सप्ताह में दो दिन जाया करते थे । लेकिन आज से पहले इन १५ सालों में यह स्थिति बन गई थी कि सालों-साल भर डाक्टर स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाते नहीं थे । लेकिन अब आप स्वास्थ्य केन्द्रों पर जायेंगे, अभी हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए नहीं हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अब वे जाकर देख लें कि १०० दिनों के अन्दर हमारे माननीय मुख्य मंत्री की सरकार जब से बनी है, जब से हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, इन १५ सालों में ५० फिसदी स्वास्थ्य उप केन्द्रों को मुर्गी फार्म बनाकर रखा गया था । आज हमारी सरकार के समय में उसकी सफाई चालू हो गई है । सभापति महोदय, सरकार के १०० दिन हुए हैं, सरकार की नीति के बारे में पढ़ा हूँ, आपको जल्द से जल्द समय में वहां डाक्टर भी उपस्थित होंगे ।

(क्रमशः)

श्री राजू कुमार सिंह :क्रमशः विशेष तौर से मैं इतना कहना चाहूंगा खासकर अपने सरकार के बारे में कि सरकार जो कार्य कर रही है, आपकी तरफ से कटौती प्रस्ताव आ रहा है, आपने अपने पंद्रह वर्ष के शासन काल में कुछ किया नहीं लेकिन अब जब सरकार कुछ करने की इच्छाशक्ति रखी हुई है तो आप भी देखिये कि आगे-आगे होता है क्या। क्योंकि अभी तो यह मात्र तीन महीने की सरकार है, सौ दिन ही पूरा किया है। महोदय, जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो फसल तुरंत नहीं काट लेते हैं, मंजर लगता है, टिकोला बनता है, बड़ा होता है तब जाकर उसको तोड़ते हैं। महोदय, सरकार अभी बनी ही है और वह जवान हो रही है, अभी खायेंगे तो खट्टा लगेगा थोड़ा पकने दीजिये तब आपको पता चलेगा कि सरकार किस ढंग से काम कर रही है।

महोदय, निश्चित रूप से मैं अपनी सरकार के बारे में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार के सभी विभाग में, खासकर स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग के बारे में मैं बात कह रहा हूँ, किसी भी विभाग की ओर आप देखें जो स्थितियाँ बनी हुई थी, जो जर्जर स्थिति बन गई थी उसे कोई एक दिन में ही ठीक नहीं कर सकता है, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उसे सटाया और स्थिति सुधर जाय, उसे सुधरने में कुछ समय लगेगा और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। महोदय, हम आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से अपने मा० लोकप्रिय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहेंगे। महोदय, मेरा पहला सुझाव यह है, जो मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट को पढ़ने के बाद लगा कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के दवा के बारे में जो आपकी अनुमानित राशि का बजट में उल्लेख किया गया है वह २ करोड़ ४६ लाख २९ हजार।

महोदय, यहाँ पर जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं दवा के बारे में, विशेष रूप से सभापति महोदय, थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है इसलिए मैं कुछ बताना चाहूंगा। हमारी बिहार सरकार ने, मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाह रहा हूँ, जो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से मेरी बात उन तक पहुंचेगी, मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी दवा जो जीवन रक्षक दवा है, अभी तो एंटीबायोटिक मिलती नहीं, गाँव के पी०ए०सी० या एडीशनल पी०ए०सी० में कहीं मिलती नहीं। महोदय, एक छोटा सा उदाहरण है जिसे मैं बताना चाहूंगा, हायर एंटीबायोटिक दवा है, डा० साहब बता रहे थे सेफीअक्सोन, पिछले साल मैं इसी तरह पटना मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ था, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर बता रहे थे, जो खरीददारी में सम्मिलित थे कि उस समय एक सेफीअक्सोन दवा आती थी जो एंटीबायोटिक है जिसका कौस्ट है बासठ रु० और जिसकी खरीदारी हुई थी उसी दर पर भारत सरकार के द्वारा। और सही मायने में देखा गया तो उस दवा को बनाने में कौस्ट आती है मात्र आठ रुपये। महोदय, एक जेनरल एंटीबायोटिक दवा, जो हमारे गाँव के गरीब लोग खेतों में, खलिहानों में काम करते हैं पैर कट जाता है, घाव ठीक कराने के लिए उनको नहीं मिलती है और घाव जो ठीक नहीं होता है वह धीरे-धीरे एक नासूर बनकर कैंसर का रूप ले लेता है। महोदय, लोगों को सर्दी-खाँसी होती है तो उसकी दवा नहीं मिल पाती है और सर्दी-खाँसी होने के बाद भी वे लोग काम करते रहते हैं और एक न एक दिन, चार-छः महीने बाद वह टी०बी० का रूप ले लेता है। महोदय, इसको रोकने के लिए सही दवा की व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, दवा की व्यवस्था आज से बीच-पच्चीस साल पहले, हमलोग उस समय छोटे थे, मिलती थी हमलोगों को याद है। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ खासकर बिहार सरकार को चाहिए कि एक अपनी मेडिसीन की फैक्ट्री को डेवलप करे जिसमें कम से कम इस तरह की जीवन रक्षक दवा बन सके। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि २२० प्रोडक्ट ऐसी है जिसको हम अपने यहाँ फैक्ट्री स्थापित करके बनाये तो पूरे बिहार को हम दवा दे सकते हैं। ज्यादा नहीं, अगर सभी माननीय सदस्यों में इच्छाशक्ति हो, एक-एक करोड़ रु० हमलोगों को प्रत्येक साल मिलता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। हम कहीं रोड में, कहीं नाले में, कहीं विकास का कार्य करने में उसको लगा देते हैं, अगर बिहार सरकार के पास पैसे की कमी है तो आप केन्द्र सरकार को लिखिये, केन्द्र सरकार भी

अगर इसमें अनुदान नहीं देती है तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप एक पत्र हम जैसे माननीय सदस्यों को लिखिये, हम माननीय सदस्यगण अपना एक-एक करोड़ रु० एक साल का देते हैं जिससे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री तैयार हो जायेगी जो कि पूरे के पूरे साल भर दवा उपलब्ध करा सकती है। आपने जो अपने बजट में दवा मद में जो राशि दी है अगर उसकी दवा खरीदी जाय तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कम से कम जीवन रक्षक दवाईयाँ बी.पी.एल.धारी जितने हैं, लालकार्ड धारी जितने गरीब हैं, उन सारों को जरूर उपलब्ध हो जायेगी। यही मेरा सुझाव है, वैसे आपलोग जैसा समझे।

महोदय, मैं सरकार के पक्ष में बोल रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ जो मेरी समझ है, क्या होना चाहिए उसके बारे में, मैं जरूर कुछ बताना चाहूंगा। महोदय, जो हमारी स्थिति बनी हुई थी उससे हम जरूर आगे निकले हैं इसमें कोई दो राय नहीं। महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने गाँव में, सीतामढ़ी जिले के कुशार में अपने दादा जी के नाम पर आज से बीस साल पहले एक अस्पताल खोला था जिसके लिए मैंने अपना छः एकड़ जमीन भी अस्पताल के लिए दिया था लेकिन उस अस्पताल की स्थिति आज कैसी जर्जर हो गई और कैसी उसकी आज दुर्दशा हो गई है, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। महोदय, पिछली सरकार का हॉस्पिटल के ऊपर ध्यान कैसा था यह किसी से छिपी हुई नहीं है।

महोदय, प्राइवेट अस्पतालों का भी आज के समय में बहुत महत्व है। कोई भी ऐसा विकसीत देश नहीं है जहाँ प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल नहीं है। महोदय, मैंने देखा है कि विकसीत देशों में, अमेरिका, रूस, जापान आदि कई देशों में भी बहुत से प्राइवेट अस्पताल हैं और विकासशील देशों में भी है। महोदय जब मैं बाहर के देश में पढ़ता था, स्टडी करने गया था उस समय टी०वी० पर, मीडिया के द्वारा यह देखने को मिलता था कि हिन्दुस्तान विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन बिहार में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारा राज्य बिहार हिन्दुस्तान से बाहर है क्योंकि बिहार पीछे के रास्ते पर चल रहा था आगे के रास्ते पर नहीं।

महोदय, बार-बार आपके द्वारा लाईट जलाकर अपनी बात समाप्त करने का इशारा किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, इसलिए मैं एक लाइन बोलने के साथ अपनी बात खतम करूंगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों से जरूर कहना चाहूंगा कि "हम जो काम करते हैं खुलेआम करते हैं, न जाने सामने वाले क्यों हमें बदनाम करते हैं"। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय-हिन्द, जय भारत।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : मा० सदस्य श्री शिवचंद्र राम।

श्री शिवचंद्र राम : मा० सभापति महोदय एवं सभी सम्मानित सदस्यगण। मैं स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, स्वास्थ्य का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और किसी अंग्रेजी के लेखक ने कहा है कि Health is wealth. महोदय, हम तो इस सदन में नए-नए आये हैं और हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ सदन में मैं बराबर सुनता रहा हूँ पंद्रह साल, पंद्रह साल। महोदय, जिस तरह से चुनाव के समय माननीय सदस्य मंच पर खड़ा होकर, चिल्ला-चिल्ला कर आवाम के बीच वोट माँगते हैं और अपनी नहीं की हुई कार्यों को, उसकी लोकप्रियता को मंच पर दर्शाते हैं और कहते हैं ठीक उसी प्रकार से गला फाड़-फाड़ कर यहाँ पर बताते हैं और विकास की बात को कहते हैं। महोदय, बिहार की जनता ने इन लोगों को हाथ में सत्ता दिया है।क्रमशः

टर्न-४१:ज्योति-बबलू

०९-०३-२००६

श्री शिव चन्द्र राम (क्रमशः): यही नहीं, नया बिहार बनाने की इन्होंने घोषणा भी की है कि नया बिहार बनायेंगे। महोदय, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारा बिहार राज्य गरीबों का राज्य है। यहाँ पर गरीब गांव में बसते हैं जिनकी बदहाल स्थिति है। वहाँ पर रहने वाले किसान, मजदूरों की ऐसी स्थिति है, अनुसूचित जाति के लोगों की ऐसी स्थिति है कि यदि उन्हें कालाजार हो जाय तो उनको काफी परेशानी हो जाती है। कालाजार की बीमारी से हमने भी महसूस किया खास करके महोदय, पटना के अस्पताल जो कालाजार के अस्पताल है ऐसे अस्पताल में सैकड़ों बार मुझे जाने का मौका मिला है तो मैंने देखा है कि जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं मजदूर तबके के लोग हैं वैसे लोग ही यहाँ अस्पताल में आकर दवा और इलाज करवाते हैं। सरकार चिल्ला चिल्ला कर जनता के बीच संदेश भेजना चाहती है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, हम वैसा काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ चिल्लाने से महोदय जनता इस बात को बिल्कुल समझ चुकी है कि आज कालाजार की जो समस्या है वह दूर होने वाली नहीं है। अब ये कहते हैं कि हमको तो अभी तीन ही महीना हुआ है, हमारा १०० दिन ही पूरा हुआ है। १०० दिन ही नहीं, ये अपनी इच्छा शक्ति यहाँ प्रदर्शित करते हैं उससे क्या पता चलता है। जो हमारा वैशाली जिला का भगवानपुर प्रखंड में एक बांथू गांव है जहाँ हर पेपर में दिया गया है पत्रिका में दिया गया है, जिसके बारे में वहाँ के जिलाधिकारी वगैरह सब जानते हैं कि मुशहर टोली में भयंकर कालाजार की समस्या है। वहाँ मुशहर समाज के दो व्यक्ति मर गए अभी भी वहाँ कम से कम २५ से ३० लोग इस बीमारी से ग्रसित होकर पड़े हुए हैं और दवाई के बिना त्राहिमाम कर रहे हैं और ये कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर तो ऐसे बोल देने से बिहार की जनता आपको ठीक नहीं कहेगी। महोदय, जो समस्या है टी०बी० की, खसरा की, डिप्थेरिया की और काली खांसी की इससे लोग परेशान हैं। हमारी सरकार टी०वी० और रेडियो पर टीकाकरण का, पोलियो का प्रचार करती है इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। प्रचार प्रसार महोदय, गांव में होना चाहिए जहाँ कि ८० प्रतिशत गरीब और मजदूर लोग रहते हैं। महोदय, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ये कहते हैं कि हॉस्पिटल में सबसे मुख्य चीज है बिल्डिंग और भवन की बात और ये नया बिहार बनाना चाहते हैं लेकिन सबसे पहले कुत्ता के काटने की दवा और सांप के काटने के दवा की सबसे पहले व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इनकी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कम से कम अस्पताल में इन चीजों की दवाईयाँ मुहैया होनी चाहिए। महोदय, मैं आपको अपने वैशाली जिले के एक घटना से सुशासन की बात कह देना चाहता हूँ कि आपके मीडिया में ९ तारीख को जो महोदय, मुहर्ररम का पर्व था उसके अवसर पर ताजिया के समय में वहाँ के महुआ जो वैशाली जिला में पड़ता है वहाँ डॉक्टर नहीं थे। मैं मरीज लेकर गया था पर वहाँ डॉक्टर नहीं थे। जिला समाहर्ता से मैंने दूरभाष पर बातें की थी उसके बाद ५ घंटे के बाद डॉक्टर पहुंचे और तबतक मरीज की स्थिति खराब हो गयी थी और आप सुशासन की बात करते हैं और इच्छा शक्ति की बात करते हैं। महोदय, हम दलित परिवार से आते हैं। आप दलित की बात करते हैं कि हम दलित को ऐसा कर दिया हम वैसा कर दिया लेकिन मैं समझता हूँ कि १०० दिन की यह सरकार है और पेपर मीडिया में ऐसा देखने को मिलता है उससे पता चलता है कि दलितों के प्रति आशा (दाई, चमईन) की बहाली में इनका अच्छा नजरिया नहीं है। अनुसूचित जाति के लोग इस धरती के स्तम्भ हैं और सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो आशा (दाई, चमईन) उसी के हाथ में केहाँ, केहाँ करते हैं, उनके साथ नजरिया नहीं बदली है उनकी बहाली में आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह): माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। मा० सदस्य श्री राम चन्द्र सिंह यादव प्रारम्भ करें।

श्री रामचन्द्र सिंह यादव: स्वास्थ्य विभाग पर चले रहे, वाद-विवाद पर बोलने के लिए मुझे मौका मिला है । माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार की ओर से जो यह सदन में वाद-विवाद लाये गये हैं, निश्चित तौर पर बदहाल बिहार तो नहीं, बीमार बिहार के लिए सबसे अहम सवाल, सबसे अहम मुद्दा पर यह बजट लाया गया । मैं जानता हूँ कि शास्त्र-अध्यात्म साक्षी है, इतिहास साक्षी है । सबसे बड़ा मुद्दा इंसान के लिए स्वस्थ रहना, हेल्थ-इज-वेल्थ । वैद्य, मंत्री जिस राज्य के अन्दर स्वच्छ हैं और ईमानदारी पूर्वक इच्छाशक्ति को मजबूत करके सेवा करें तो निश्चित तौर पर से राज्य के उस प्रदेश के उस गांव की खुशहाली लाने में कोई बहुत बड़ा समय नहीं लगता है । आज उसी सवाल को ले करके यह बहस चल रही है । पूरे बिहार की स्थिति सर्वोपरि है तथा आज यह कहना चाहूंगा कि इस अनुपात में कम से कम केवल दिशा देना चाहता था । डॉक्टर और पेसेंट के अनुपात क्या हैं और भविष्य में बजट पर क्या होना चाहिए । परन्तु, यह अनुपात नहीं लाया गया फिलहाल में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पूरे बिहार के अन्दर जो स्थिति, परन्तु स्थिति पूर्व के सभी सदस्यों द्वारा बातें लायी गयीं और आपके माध्यम से सरकार तक पहुंची । माननीय मंत्री महोदय चिंतन-मनन कर रहे हैं । एक गाँव के बीमारी से ले करके दिल्ली तक दिल्ली में एम्स में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरगंज में जाइये । जाने के बाद हिन्दुस्तान के जितने पेसेंट होंगे उसमें ६० प्रतिशत सिर्फ बिहार के हुआ करते हैं । चाहे जिस किसी विभाग के पेसेंट हों । आखिर क्या कारण है कि ७ मेडिकल प्रावधान लाया गया है । हमारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लाया गया है । २१०० बेड का प्रावधान लाया गया है । परन्तु आज मैं समझता हूँ कि आप एक बात ले लेते हैं, प्रत्येक महीने की बातें लेकर कही जाती है, १५ साल तीन महीने की कंपेयर की जाती है । इच्छाशक्ति मजबूत होने के साथ जो कुछ हो रहा है । आपके द्वारा यह निर्णय लिया गया है, यह निर्णय निश्चित तौर पर काबीले तारीफ है, परन्तु वर्तमान में सिर्फ मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, पीड़ित, शोसित अल्पसंख्यक के लिए जो गरीबों के लिए लाल कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए जो दवाई की व्यवस्था की जाती है और पूरे बिहार के अन्दर जो दवाई बांटी जाती है, उसमें लूट-खसोट होता है, उसमें अंकुश लगाने की व्यवस्था और आपके माध्यम से विशेष तौर पर सरकार का और माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा और यह बात सरकार को सदन में बताना चाहिए और उसको यहाँ पर लाने की जरूरत है । जिस तरह से शिक्षा विभाग में आरक्षण के तहत आवासीय विद्यालय या आवासीय कई तरह की व्यवस्था की जाती है गरीबों के लिए, उसी तरह आपके द्वारा गाँव के गरीबों के लिए केन्द्र बना करके गांव में दबाइयाँ बांटी जाती है, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ । क्रमाशः.....

विजय ।

श्री रामचन्द्र सिंह यादव: क्रमशः..... मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कम से कम पूरे बिहार के अंदर सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के बगल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बगल में ऐसी कोई व्यवस्था हो सरकार की ओर से जिसमें सिर्फ गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का ही इलाज होने का प्रावधान हो । मैं देखा हूँ कि किसी अस्पताल में जाने के बाद हमारे परिवार के कोई लोग चले जायें सरकारी अस्पताल में और एक गरीब दलित, शोषित, पीड़ित चला जाता है हमारे परिवार के मेम्बर को देखते हुए हमारी पर्ची जाती है डा० साहब हमारी पर्ची को एक्सेप्ट करते और नं० में कराहता रहता है चिल्लाता रहता है ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): मा० सदस्य, श्री मनोज कुमार सिंह ।

नहीं हैं क्या चलिये । माननीय सदस्य, श्री जय कुमार सिंह, १० मिनट ।

श्री जय कुमार सिंह: सभापति महोदय, आज मैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाये गए स्वास्थ्य बजट के पक्ष में खड़ा हूँ । महोदय, जब भी यहां बजट भाषण में चर्चाएं होती हैं तो इन चर्चाओं में १५ वर्षों के कारनामे का वर्णन हो ही जाता है । और वो क्यों न हो, आपके वर्णन किये बिना पक्ष में रहे हुए लोगों का सन्देश भी पूरा नहीं हो पाता है । क्योंकि १५ वर्षों में बिहार की स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाय तो सारी आधारभूत संरचनायें भंग हो चुकी थी गांवों से लेकर प्रमंडलीय हॉस्पिटल तक सारी व्यवस्थाएं चरमरा गयी थी । १५ सालों में प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग अपने को स्वस्थ तो रखे लेकिन बिहार की जनता बिहार की गरीब जनता को अस्वस्थ करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ा । मान्यवर, हमारी सरकार के आए हुए महीन हुआ हैं । स्वास्थ्य विभाग की सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कम समय में जो हमारे मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कदम उठाया है वह अति सराहनीय है । मैं इसके लिए इनके बजट के पक्ष में आज खड़ा हूँ । मान्यवर, बिहार में २२०० डाक्टर की रिक्तियां हैं । हम रोहतास जिला से आते हैं । १०७ डाक्टर की पोस्टिंग है मात्र ७० डाक्टर कार्यरत हैं । हम विक्रमगंज विधान सभा क्षेत्र से आते हैं । विक्रमगंज रेफरल हॉस्पिटल में ८ डाक्टर की नियुक्ति है मात्र ३ कार्यरत हैं ड्रेसर नहीं है, कम्पाउंडर नहीं है । वहां का एम्बुलेंस खराब पड़ा हुआ है चूंकि इस १५ साल के राज्य में कभी किसी हॉस्पिटल में सरकार ने एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं किया । विक्रमगंज में एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई तो हमारे ही पार्टी के सांसद मानीनय अजीत कुमार जी के द्वारा एक एम्बुलेंस दिया गया और उस एम्बुलेंस के रख रखाव के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है चूंकि वह एम्बुलेंस सांसद निधि मद से दिया हुआ है । हमारी सरकार ने इसके बारे में बहुत उचित कदम उठाया है । कम समय में मैं यह बता देना चाहता हूँ हमारी सरकार ने ध्वस्त आधारभूत संरचना को दृढ़ करने के लिए सारे हॉस्पिटलों को मजबूत किया जा रहा है सारे हॉस्पिटल में जिला में एक चलन्त भान एम्बुलेंस दिया जा रहा है जो उपकरणों से लैश रहेगा । मोतियाबिंद की आपरेशन की व्यवस्था रहेगी इतना कम दिनों में हमारी सरकार ने व्यवस्था किया है । हमारी सरकार ने स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बिहार की जनता को आश्वस्त कराना चाहते हैं कि उनके स्वास्थ्य के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कैसे व्यवस्था किया जाय । उसकी सारी व्यवस्थायें हमारी सरकार तीव्र गति से कर रही है । हम चाहते हैं सरकार ने ०४-०५ में जो बजट पेश किया था और हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है मान्यवर स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में इस वर्ष के योजना मद में ३२६ करोड़ तथा गैर योजना मद में ९१४ करोड़ अर्थात् कुल १२४० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । वर्ष २००४-०५ में इस प्रक्षेत्र में मात्र ७८३ करोड़ रुपया का प्रावधान था इस तरीके से योजना मद में निर्माण के लिए २० करोड़ और प्रमंडलीय अस्पतालों को २५ करोड़ और सदर अस्पतालों के भवन के लिए ३३ करोड़ रुपया दिया गया है । दवा और अस्पतालों के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए २८१ करोड़ रुपया दिया गया है इतना ही नहीं हमारी सरकार ने जो १६ करोड़ की राशि विमुक्त किये हैं महोदय उसका एक छोटा आंकड़ा है ।

क्रमशः

श्री अजय कुमार सिंह : ...क्रमशः ...

उसका एक छोटा आंकड़ा है कि मुजफ्फरपुर कालेज अस्पताल में १.७५ करोड़ रुपये उपकरण के लिये अस्पताल में भवन निर्माण के लिये २.६५ करोड़ रुपये दिया है । अनुग्रह नारायण मेडिकल कालेज अस्पताल में १.२६ करोड़ और अलग से पुस्तक के लिये

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

३६ लाख रुपये दिया गया है । एन०एम०सी०एच० में उपकरण के लिये और पुस्तकालय के लिये २६.७२ लाख रुपये दिया है, यह हमारी सरकार का सराहनीय कदम रहा है । विक्रमगंज में रेफरल हास्पिटल के लिये ९५ लाख और प्राथमिक चिकित्सा दवा के लिये ७५ लाख रुपये दिया है और उपकरणों के लिये, दवाओं के लिये यह व्यवस्था की गयी है । हमारी सरकार, न्याय यात्रा के माध्यम से घूम घूम कर मुख्यमंत्रीजी और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदीजी ने जो कहा था, उसकी कल्पना को हमारे स्वास्थ्य मंत्री धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं । मान्यवर, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि देशी चिकित्सा के लिये हम केवल बड़ी बातें, चर्चा यहां होती हैं, हम अभी भी अपने बजट का ९० प्रतिशत अंग्रेजी चिकित्सा पर खर्च करते हैं लेकिन यह भारत गांवों का देश है । वनों में तरह तरह की वनस्पतियां पायी जाती हैं, मान्यवर, देशी चिकित्सा में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक में तीन चिकित्सा पद्धतियां हैं । एक सुझाव के तौर पर मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि यह प्राचीन धरोहर है, प्राचीन काल से आयुर्वेद से सर्व सुलभ चिकित्सा की जा रही है, भारत में अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और आयुर्वेद बहुतायत से पाया जाता है । आयुर्वेद शास्त्र में सहस्रों वर्ष पूर्व चरक संहिता जिसमें यह कहा गया है, मान्यवर, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और उत्क्रम व्याधि यानी रोगों से मुक्त, ऐसा ही अंग्रेजी चिकित्सा में भी दो ही प्रावधान रखा गया है मान्यवर । प्रीवेंटिव और क्यूरेसिव के बारे में, डाक्टर सुनील ने विस्तारपूर्वक बताया है ।

मान्यवर, हम चाहते हैं कि बिहार में देशी चिकित्सा प्रवृत्ति की स्थिति दिन प्रतिदिन हास होती चली गयी, इन पंद्रह सालों में जो हमारे आयुर्वेद की संस्थाएं थीं ध्वस्त कर दी गयीं, मान्यवर अभी अभी रामदेवजी देश में आयुर्वेद के माध्यम से अपना परचम फहराने का काम किया है, सबसे पहले दवाओं औषधियों के नाम पर हम प्रसिद्ध मानते जा रहे थे तो हमारा प्रथम काम था होम्योपैथी और आयुर्वेद के माध्यम से भारत जाना जाता है, मैं मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूँ, आप अपने भाषण में इसके बारे में विस्तारपूर्वक बतायेंगे और क्या कहें, इसका रूप बदल भारत औषधियों के रूप में जान ले इसके बारे में प्रयास करेंगे बजट में ।

....क्रमशः

टर्न-४४/राजेश/९.३.२००६

श्री अजय कुमार सिंह, क्रमशः:- श्री म. म. म. म. महोदय, हम चाहते हैं कि १९२६ में संचालित चिकित्सा राजकीय आर्युवेद कॉलेज पटना एवं चार अन्य बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा और बक्सर और निजी क्षेत्रों से जो अधिग्रहण किया गया था उस कॉलेज को, मान्यवर उसकी स्थिति बहुत खराब है, उसकी स्थिति हम दिल्ली के मापदंड के अनुकूल सृजित पदों को

(व्यवधान)

अध्यक्ष:- अब आप अपना वक्तव्य समाप्त करें माननीय सदस्य ।

श्री अजय कुमार सिंह:- महोदय, सृजित पदों को निर्धारित स्नातकोत्तर अधिकारी से भरा जाय । मैं ऐसा आपके माध्यम से अपने मान्यवर मंत्री जी से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष:- ठीक है । अब माननीय सदस्य श्री राम विनोद पासवान जी, आप सिर्फ दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे ।

श्री राम विनोद पासवान:- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पी०एम०सी०एच० के हालात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । पी०एम०सी०एच० में स्वीकृत ड्रेसर का २८ पद, कार्यरत मात्र १०, जले और घायलों को जो पी०एम०सी०एच० में संख्या बल है, एक ड्रेसर पर ४७, जबकि ड्रेसर को प्रतिदिन मरीज को मलहम, पट्टी या ड्रेसिंग करना है, लेकिन आज हालात क्या है ? प्रतिदिन के बदले तीन-तीन रोज के बाद मरीजों का ड्रेसिंग किया जा रहा है । आज पी०एम०सी०एच० में बदबू का गंध और क्रन्दन सा महसूस किया जायेगा, जरा मंत्री जी इसको देख लें ।

अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के अन्तर्गत यक्ष्मा पीड़ितों की जो पंजीकृत संख्या है, उसका जो औसत संख्या है, वह है पेशा से बीड़ी मजदूर और बीड़ी मजदूरों को बेहतर इलाज की व्यवस्था । जब राज्य एक था तो तिलैया में उसका अस्पताल था । राज्य का बँटवारा हो चुका और तिलैया के स्तर का राज्य में यक्ष्मा रोगियों को, बीड़ी मजदूरों के लिए खासकरके इलाज की व्यवस्था नहीं है । हम जानना चाहेंगे मंत्री जी, कि तिलैया स्तर का यक्ष्मा पीड़ित रोगियों का अस्पताल निर्माण करना चाहते हैं कि नहीं ।

महोदय, राज्य के अंदर कालाजार रोगियों को जो दवाई एस्टीवानेट दिया जा रहा है, वह कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है और जो अभी दवाई अलग से मेहगें रेट पर खरीदा जा रहा है वह है फंगीजोन । फंगीजोन दवाई की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में माननीय मंत्री जी करेंगे कि नहीं ।

माननीय मंत्री जी का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं नवसृजित जो अनुमंडल हैं, जो प्रखंड हैं, उन नवसृजित अनुमंडलों और प्रखंडों में अस्पताल का सृजन करते हुए चिकित्सकों का पदस्थापन करना चाहते हैं या नहीं ।

हम यह भी मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि कहीं भी आकस्मिक कार्य में प्रखंड के अंदर स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ हैं, वहाँ गाड़ी नहीं है । गाड़ी के अभाव में वे समुचित समय पर गाँव के अंदर नहीं जा पाते हैं, वहाँ गाड़ी की व्यवस्था किया जायेगा कि नहीं । रोगियों को दूसरी जगह ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है । एम्बुलेंस की व्यवस्था प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रों में किया जायेगा कि नहीं ?

अध्यक्ष:- अब आप स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य । अब माननीय सदस्य श्री गोपाल कुमार अग्रवाल । आप एक मिनट में अपनी बात को रखिये ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल:- अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय आज हमारा प्रांत कर्ज ले रहा है, सिर्फ इसलिए कि डाक्टरों को समय पर दरमाहा देना है, हॉस्पिटलों को दवाई उपलब्ध करानी है, अतिरिक्त एवं उच्च स्वास्थ्य केन्द्रों को बनाना है, क्यों, इसलिए की डाक्टर आज प्राइवेट प्रैक्टिस में लीन है, दवाएँ बाजारों में बिक रही हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर स्वास्थ्य केन्द्रों में देखियेगा गाँव देहात में, तो गोरु और बकरी

बाँधने का काम चल रहा है,आजादी के ५८ सालों के बाद भी आज हम बिहार के ग्रामीणों को सस्ता स्वास्थ्य देने के लिए भी आज हमारे पास व्यवस्था नहीं है । हलॉकि सरकार ने कुछ अच्छे निर्णय लिये हैं,हम स्वागत करते हैं सरकार के उन निर्णयों का,आज हमारे यहाँ महोदय जनगणना के आधार पर २००१ में जो जनगणना हुई थी,१९९१ से लेकर २००१ के बीच में जो हमारी जनसंख्या दर बढ़ी है,वह २८.४ प्रतिशत है,उसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति ४२ रुपये का प्रावधान सरकार ने किया है,आज भी हमारे यहाँ २१ प्रतिशत व्यक्ति को इलाज के लिए ९ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है,२८ परसेंट व्यक्तियों को १२ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और २७ परसेंट व्यक्तियों को ५ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है । माननीय महोदय,आज प्राथमिक केन्द्रों में डाक्टरों की कमी,उप स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की कमी.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष:- अब आपका समय समाप्त हुआ,अब आप दूसरे दिन बोलियेगा । अब माननीय सदस्य श्री फुलेना सिंह,आप तीन मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे ।

श्री फुलेना सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में स्वास्थ्य पर बोलने का मौका मिला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य का हाल है पूरे बिहार में, वह सबों से छिपा हुआ नहीं है। मैं पूरे बिहार की बात नहीं करना चाहता हूँ खासकर अपने जिले के बारे में माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि हमारे यहां जो अस्पताल है-- नये अस्पताल खोलने की बात हो रही है लेकिन पुराने अस्पताल जो चल रहे हैं, इन २-३ महीनों के प्रयास के बावजूद भी गतिविधि में कोई अंतर नहीं है। जहां तक दवा की बात है, दवा फाईल और कागज में ही बांटे जाते हैं। डाक्टर समय पर नहीं आते हैं। खासकर के देहाती एरिया में डाक्टर सप्ताह में एक दिन आते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह गुजारिश करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य की जो बुनियादी समस्या है और इससे संबंधित जो स्वास्थ्य विभाग है अन्य विभागों, अन्य मंत्रालयों से ज्यादा अहम स्वास्थ्य विभाग है। अन्य सारे जो विभाग हैं, उनसे मानव का भरण पोषण किया जाता है और इस विभाग से मानव जिंदगी और मौत की अपनी सौदा करता है। इसलिए यह विभाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महोदय, मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि हम यहां भाषण देते हैं और पक्ष और विपक्ष की बातें करते हैं लेकिन जिस समय हम उनसे वोट मांगते हैं, उस समय हमें याद होती है कि गरीब जनता और गरीबी की बुनियादी हालत क्या है? जब हमलोग जीतकर यहां चले आते हैं तो भी उनकी बुनियादी हालत वही रह जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आधे से अधिक लोग जिनके पास दो हजार रुपया भी नहीं होता है, दो हजार रुपया नहीं होने के चलते अपने घर में ही भगवान के सामने सिर झुका कर मौत को गले लगा लेते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, मैं बहुत सलाह नहीं देना चाहता हूँ, विशेष सलाह नहीं दूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आधे से अधिक आबादी दो चार हजार रुपया के चलते अपना दम तोड़ देते हैं। इसका उपाय कैसे हो। हम प्रतिनिधि जाते हैं तो हल्ला करते हैं -- अस्पताल के जो सिविल सर्जन हैं, जो कलक्टर हैं उनके माध्यम से पैसा दिया जाता है परन्तु वे सुनते नहीं हैं। कैसे इसमें तीव्रता लायी जाये चाहे पंचायत के माध्यम से या कमिटी के माध्यम से। जिस प्रकार से यहां करोड़ों करोड़ रुपये जो खर्च होते हैं, वह जनता तक पहुँचे। आज ५० वर्ष से ज्यादा आजादी के हो गये फिर भी उन्हें चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब हम वोट लेने जाते हैं तो अमीर हो या गरीब हो दोनों का वोट बराबर होता है। आज लोकतंत्र में दोनों का हक बराबर है। आज उन्हीं के वोट को लेकर हमें यहां आने का अधिकार मिला है। इसलिए महोदय हम निवेदन करते हैं कि आपके अंदर नया विहार बनाने की जो कल्पना है, स्वस्थ बिहार बनाने की जो कल्पना है, उसकी तरफ ले चलें। हमारे जो प्राइवेट डाक्टर्स हैं उनके पास वहीं जाते हैं जिनके पास पैसा है। आज स्थिति यह है कि गरीबों को सरकारी अस्पताल पर से विश्वास उठ गया है -- हमारे गरीब लोगों को सरकारी अस्पताल और सरकारी डाक्टर्स से विश्वास उठ गया है-- हमारे यहां रेफरल अस्पताल है, बड़हिया और लखीसराय में, लेकिन रामदेव बाबू माननीय सदस्य बोल रहे थे कि वहां डाक्टर नहीं आते हैं, आदमी नजर नहीं आते हैं, १०-५ बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है। हमलोगों ने सिविल सर्जन और कलक्टर के यहां बैठक भी किया, बातें भी हुई लेकिन बातें टाय-टाय फिस हो जाती है। बड़हिया और लखीसराय अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है और दवा की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर समुचित व्यवस्था नहीं हुई तो जनता आंदोलन भी करेगी भविष्य में। मरता क्या नहीं करता। रोड और बिजली पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। लेकिन जीवन और मौत से लड़ने के लिए चिकित्सा हेतु उतना पैसा नहीं जाता है। नये विधायक के लिए विशेष भाषण देना उचित नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उनका जो हक है उनका हक पर बात हो, पक्ष विपक्ष की बात न होकर विकास की बात हो और इसपर माननीय मंत्री विशेष रूप से ध्यान देंगे और लखीसराय पर विशेष रूप से ध्यान देंगे।

सरकार का जवाब

श्री चन्द्र मोहन राय, मंत्री - अध्यक्ष महोदय, मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय शकुनी चौधरी जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का, माननीय सदस्य डा० कनौजिया जी का और डा० सुनिल जी का जिन्होंने अपने रचनात्मक सुझावों विधान सभा के पटल पर रखें।

महोदय, मैं जो बातें सरकार की ओर से कहूँगा उसमें निश्चित रूप से आपकी अधिकांश बातों का समाधान हो जायेगा। समय सीमित है। शायद एक-एक करके सभी बातों का जवाब देना मेरे लिये संभव नहीं है और एक बात के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे और सदन से क्षमाप्रार्थी हूँ कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हमारा प्रतिवेदन निकल नहीं पाया और वह आज वितरित नहीं हो सका। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि सदन में ही वह वितरित कर दिया जायेगा और इसमें जो देरी हुई है उसके लिए सब लोगों से दोबारा माफी चाहता हूँ।

श्री जगदानन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि तकनीकी गड़बड़ी से इनका प्रतिवेदन नहीं निकला है। लेकिन तकनीकी सहारा लेकर पूरे देश के पैमाने पर किस तरह से भ्रूण हत्यायें बच्चियों की गयी है, इसको दिखाया जा रहा है। इसलिए हमलोग सदन का बहिर्गमन करते हैं।

व्यवधान

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन का बहिर्गमन किया।)

अध्यक्ष- माननीय मंत्री, आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री चन्द्रमोहन राय, मंत्री - अध्यक्ष महोदय, आगामी कुछ मिनटों में, जो स्वास्थ्य विभाग मुझे बिरासत में मिला है और उसके वर्णन को शायद हमारे मित्र सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने सदन से वाक-आउट करने का बहाना बनाया है। महोदय, ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था, बिल्कुल अराजकता की स्थिति- दो उदाहरण दूँगा अध्यक्ष महोदय, १९९७ में स्वास्थ्य विभाग ने बी०पी०एस०सी० के चेयरमैन को एक पत्र भेजा एक हजार डाक्टरों की बहाली के लिए। बी०पी०एस०सी० ने रीटेन परीक्षा एवं इन्टरव्यू लेने के बाद लगभग एक हजार डाक्टरों का पैनल बनाया और उसने स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया। उसके बाद स्वा०विभाग ने लगातार कई सालों तक इसे लटकाये रखा। जब प्रभावित डाक्टर्स हाईकोर्ट की शरण में गये तो तीन डिफरेंट एफिडेविट दिये गये, हाईकोर्ट में, जिनमें रिक्तियों का अलग-अलग वर्णन किया गया और जब उस चिट्ठी के आधार की खोज हुई स्वा०विभाग में कि किस आधार पर एक हजार रिक्तियों की सूचना बी०पी०एस०सी० को दी गयी थी तो उसका कोई आधार स्वा०विभाग में मौजूद नहीं था। जिस तरह से यह स्वा०विभाग को चलाया जा रहा था।। आज लगभग २० सालों से न डाक्टरों की बहाली हुई, न पारा मेडिक्स की बहालियां हुई, यह विभाग केवल ट्रांसफर-पोस्टिंग विभाग बनकर रह गया था। पोस्टिंग और ट्रांसफर एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। स्वास्थ्य विभाग का मुख्य जिम्मेवारी है स्वा०नीतियाँ करना और उसको इम्प्लीमेंट करना और स्वा०नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में आ रही कठिनाईयों को दूर करना। विपक्ष के माननीय सदस्य आज गरीबों की बात कर रहे थे, सरकारी स्वा०स्वायें ही गरीबों के लिए कायम की जाती है, जो अपेक्षाकृत हमारे समृद्ध समाज के लोग हैं, जो अपने लिये स्वा०सेवायें खरीद सकते हैं, उनके लिए शायद सरकारी स्वा०सेवायें की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हम सारी स्वा०सेवायें का ताना बाना इसलिए बुनते हैं कि हमारा जो समाज गरीब है जो अपने लिये इलाज नहीं खरीद सकते हैं, अपने लिये दवा नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए हम इलाज उपलब्ध कराये और उसके लिए हम दवा उपलब्ध कराये। आज अपने मुंह मिया मिट्टू बन रहे थे, शकुनी बाबू, अपनी सरकार का अपने विभाग का बखान कर रहे थे। अपने मुंह से तो अपनी तारीफ सब करते हैं।

क्रमशः

टर्न-47/सत्येन्द्र/9-3-06

श्री चन्द्रमोहन राय(मंत्री)(कमशः)अध्यक्ष महोदय,जो केन्द्र में वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है,डॉ० अम्बु मनी रामदास, हमारे प्रतिद्वंदी राजनीतिक गठबंधन के मंत्री है, उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य विभाग के बारे में क्या कहा है? ये आपको दो शब्दों में बतलाना चाहता हूँ।अभी कुछ दिन पहले ये आये थे, एक उच्चस्तरीय डेलीगेशन लेकर यहां आये थे, उसमें हेल्थ सिक्रेटरी थे, स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी भी थे और यहां आकर गेस्ट के रूप में कहना एक औपचारिकता हो सकती है लेकिन यहां से लौट कर जाने के बाद जो बड़े-बड़े दिल्ली में हेल्थ फोरम है वहां उन्होंने बिहार के बारे में क्या कहा- इसको मैं आपको बतलाना चाहता हूँ The Bihar government is intelligently using its resources and is busy putting in place the required infrastructure to offer healthcare services to the people.It is building hospitals,medical colleges and educational institutes to produce paramedical staff.These efforts will show results in the next one year....We have resources available and the Prime Minister has assured me that money will not be a problem.हमलोग ऐसा नहीं है,माननीय अध्यक्ष महोदय कि दूसरे की मदद मिलने पर भी धन्यवाद देने की औपचारिकता नहीं रखते हैं। हम इतने कृतज्ञ नहीं हैं कि एन.डी.ए. सरकार ने इनकी इतनी मदद की और उसका जाकर हमारे समाज में इन्होंने उल्टा प्रचार किया।अगर आज प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिये गये इंसेटिव पर, अगर आशा की किरण बिहार में देखते हैं और हमको मदद करना चाहते हैं तो हम प्रधान मंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को अपनी तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से धन्यवाद जरूर दूंगा।वे लोग यहां आये थे और हमारे साथ,माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी वार्त्ता हुई, उन्होंने कहा कि मैं आज बिहार में आकर बहुत प्रसन्न हूँ और बिहार में स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए जो पहल किये जा रहे हैं उससे आशा की किरण बनी है और आज आपको बता देना चाहता हूँ इसी बजह से आज हमलोगों ने पटना में एक विश्वस्तरीय मेडिकल कॉलेज इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थापित करने का फैसला लिया है।एक बहुत बड़ा नर्सिंग स्कूल भी स्थापित करने का फेसला लिया है।हम चौतरफा प्रयास कर रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए, आप सबने देखा है हमने जो बजट में उपबंध किया है उसमें स्वास्थ्य उप केन्द्र से लेकर हमारी सबसे छोटी यह जो इकाई है वह दूर दराज के इलाके में स्थित है उससे लेकर के पी.एम.सी.एच. तक आई.जी.आई.एम.एस. तक सब लोगों का इसमें ख्याल रखा है और आज मैं बताना चाहता हूँ, एक मंत्री के रूप में, ट्रांसफर और पोस्टिंग की जहां तक बात है, आज तीन महीने गुजर गये, मैंने ट्रांसफर ओर पोस्टिंग का एक फाईल छुआ तक नहीं है।यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमारा विभाग करेगा, कहीं किसी के साथ अन्याय हुआ तो मैं हस्तक्षेप कर सकता हूँ।माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप कर सकते हैं लेकिन पोस्टिंग और ट्रांसफर को व्यापार बना ले

यह कतई उचित नहीं है। माननीय शकुनी जी हमें एडवाइस दे रहे थे कि इनको बहुत कुछ सीखना बाकी है। माननीय अध्यक्ष जी मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि सीखने से किसी को भागना नहीं चाहिए, यह जिन्दगी की निरन्तर प्रक्रिया है, रोज हम कुछ न कुछ सीखते हैं अगर हम समझ गये कि बहुत जानते हैं तो उसी दिन हममें बौद्धिक जड़ता आ जायेगी और हमारा विकास रूक जायेगा लेकिन माननीय शकुनी जी और पूर्व के मंत्रियों ने जो पाठ हमारे विभाग में छोड़कर गये हैं वह पाठ सीखने से बेहतर होगा कि मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूँ। यह पाठ मैं कभी नहीं पढ़ूँगा और नीतीश कुमार जी ने ईमानदारी का सुचिता का जो मापदंड कायम किया है उसके आधार पर ही मैं स्वास्थ्य विभाग का सुधार करूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने आगामी आने वाले समय में, अभी कुछ कैटेगरी के अस्पतालों को हमने चिन्हित किया है जिसको 24 घंटे चालू रहने वाले अस्पतालों में विकसित करने का कार्यक्रम है। (कमशः)

श्री चन्द्र मोहन राय, मंत्री : क्रमशः हमारे पास डॉक्टरों की कमी है । हमारे पास पारा-मेडिक्स की कमी है जिसकी वजह से हम सभी तरह के कैटेगरी के अस्पतालों में उनकी नियुक्ति करके उनको अभी चालू नहीं रख सकते । इसीलिए जब तक हम नयी नियुक्तियां नहीं करते, तब तक हमने सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हमने अपना ध्यान केन्द्रित करने का फैसला किया है । हमने, जो भी हमारे नव-सृजित जिले हैं, वहां हम नये सदर अस्पताल बनाने जा रहे हैं । हमने बजट में उपबन्ध कर दिया है, और वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके लिए हमने राशि भी रीलीज कर दी है । उसी तरह से नव-सृजित अनुमंडलों में जहां कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, वहां पर नये सिरे से हम अस्पताल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जहां पहले से रेफरल अस्पताल बने हुए हैं, उन अस्पतालों को हम उत्क्रमित करके अनुमंडलीय अस्पताल का उसको रूप दे रहे हैं । इसके अलावा हर जिला सदर अस्पताल में हम ३४लाख की लागत से एक इन्टेन्सिव केयर यूनिट की हम स्थापना कर रहे हैं । इसके लिए पैसे का आवंटन कर दिया गया है और काम शुरू कर दिया गया है । हम हर सदर अस्पताल में रेडियोलौजी और पैथोलौजी की सुविधा सुनिश्चित कर लिए हैं । और यह अनवरत् चलता रहेगा । सुचारु रूप से चलता रहेगा । इसीलिए हमने इसको निजी क्षेत्रों से आउटसोर्स करने का निर्णय लिया है । अभी तत्काल हमारा डा० दिलीप सेन के साथ एक अनुबंध हुआ है जिसमें तत्काल १९ जिलों में डा०दिलीप सेन के द्वारा पैथोलौजी की सेवा शुरू की जा रही है । हमने यह भी ध्यान रखा है कि जो ये सुविधा प्रदान की जाएगी निजी क्षेत्रों से, उसमें हमारे गरीब मरीजों पर भार नहीं पड़े । इसीलिए उसमें हमने एक शर्त रखी है कि अस्पताल के जो मरीज होंगे, उनको हमारे द्वारा तय की गई दर पर उनको देखना होगा, फिर, उसके अलावा जो मरीज होंगे, उसको मार्केट रेट पर देख सकेंगे । और, इस सुविधा को हम निश्चित ही अगले कुछ दिनों में ३८जिलों में कायम करना चाहते हैं । उसी तरह से, हम नव-सृजित प्रखंडों में नया अस्पताल बनाने जा रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उसके लिए हमने २२लाख प्रति अस्पताल का प्रावधान किया है । जहाँ अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनको प्रोन्नत करना है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में, वैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए हमने ३४लाख दिए हैं । इसी तरह से, हमने पूरे इलाके में सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन बनाने का निर्णय लिया है । और उसकी शुरुआत इसी साल से कर दी है और इस साल के बजट में ७५१ स्वास्थ्य केन्द्रों का नया भवन बनने जा रहा है जिसके लिए प्रति स्वास्थ्य केन्द्र हमने साढ़े छः लाख बजट में प्रावधान किया है । हम हाईकोर्ट की वजह से, डॉक्टरों की बहाली माननीय अध्यक्ष जी, नहीं कर पा रहे थे । आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की पहल से, कानूनी पैरवी से हमें जो सिंगल बेंच का प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको हमें डिविजन बेंच ने एलाउ कर दिया है । और, आगामी अप्रैल माह में ही, जिस बी०पी०एस०सी० पैनल की चर्चा हमने की थी, उस पैनल के आधार पर तत्काल लगभग ढाई सौ डॉक्टरों की बहाली हम अप्रैल माह में करने जा रहे हैं । इसके अलावा भी लगभग ५९४ डॉक्टरों के पद हमने विहित किए हैं, उसके बारे में भी तैयार करके सरकार नीतिगत निर्णय लेगी । बहाली तो करना है लेकिन बहाली का स्वरूप क्या होगा, इसका भी हम निर्णय लेकर उसको भी हम जल्द-से-जल्द भरने की कार्यवाई करेंगे । अभी पारा-मेडिक्स को बहाल करने का फैसला इस सरकार ने लिया है, ५७०० पद अभी रिक्त हैं पारा-मेडिक्स के, उसकी बहाली हम अनुबंध के आधार पर आगामी कुछ दिनों में करने जा रहे हैं । इसीलिए हम समझते हैं कि आगामी तीन-चार-पांच महीनों में हमारे डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाएगी, पारा-मेडिक्स की नियुक्ति हो जाएगी और वह जो शिकायत रहती है आमतौर पर, डॉक्टरों के बारे में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों के बारे में, नहीं बैठते हैं, यह कम-से-कम रिक्तियां भर दी जाएगी । और, हमने डॉक्टरों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पुराना ऐक्ट था, ऐक्ट हमने नहीं बनाया, १९८३ का बना हुआ ऐक्ट था लेकिन किसी बिहार सरकार के मंत्री ने हिम्मत नहीं दिखायी इस ऐक्ट को लागू करने की । डॉक्टरों के विरोध के कारण और इसमें इरादा मेरा डाक्टरों को प्रताड़ित करने का नहीं, हम डॉक्टरों को सुधर जाने का मौका देना चाहते हैं...क्रमशः...

श्री चन्द्रमोहन राय, मंत्री : ..क्रमशः.. हम डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी रोक नहीं लगाना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि वे ८ घंटा की ड्यूटी करें और ८ घंटे की ड्यूटी करने के बाद जो समय बचे तो उसमें वे अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करें लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ड्यूटी कहीं, नियुक्ति कहीं, क्लिनिक कहीं, यह सरकार नहीं चलने देगी और हर हालत में इसको बन्द किया जायेगा ।

महोदय, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने प्राइवेट क्लिनिकों द्वारा की गयी मनमानी की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पटना के और बिहार के मशहूर चिकित्सकों का एक दल बनाया है, उनकी बैठकें भी शुरू हो गई हैं और उनको निजी क्लिनिक चलाने के लिए क्या मानक हो, इसको तैयार करने की जिम्मेवारी हमने उनको दी है । उनकी रिपोर्ट में समझता हूँ कि इस महीने के अन्त तक में प्राप्त हो जायेगी और निश्चित रूप से उनकी अनुशंसा के आधार पर सरकार रेगुलेटरी मेजरशिप लायेगी, अगर इसके लिए ऐक्ट भी लाना पड़ेगा तो हम लायेंगे और उनको नियंत्रित करेंगे जिससे कि वे मरीजों को एक्सप्लॉइट करके उनसे उगाही का काम नहीं कर पायें । यह हम निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में करेंगे ।

महोदय, ब्लड बैंक की जो बात है, इसका जो अवैध व्यापार चल रहा था, उसपर हमने रोक लगाया है । हमने एक मोडल ब्लड बैंक, अध्यक्ष जी, मैं चाहूँगा माननीय सदस्यों से भी आग्रह करूँगा कि कभी आपको मौका मिले जो कंकड़बाग जाइये और इसको देखिये, जिस तरह से वह ब्लड बैंक फंक्शन कर रहा है, उसको देखिये । बहुत बढ़िया तरीके से वह काम कर रहा है और आज पटना की सारी जरूरतों को वह पूरा करने में समर्थ है । वहाँ सारा मोडर्न मशीन लगाया गया है और आज पटना में स्थापित उस ब्लड बैंक ने एक मानदंड स्थापित किया है । जिस तरह से स्वच्छ ब्लड, शुद्ध ब्लड जो मरीजों को, खासकर एड्स के खतरे को देखते हुए यह बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, शुद्ध ब्लड लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, यह अपने-आप में एक बहुत आदर्श संस्था के रूप में विकसित हो जायेगा । महोदय, आगे आने वाले समय में हम हर सदर अस्पताल में एक ब्लड बैंक की स्थापना करने जा रहे हैं ।

महोदय, हम ब्लॉक स्तर पर अभी तत्काल एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने जा रहे हैं, इसकी बात लोगों ने कही थी, एम्बुलेंस हो, जेनरेटर हो, टेलिफोन हो, इसकी व्यवस्था ही नहीं की है बल्कि हमने इसके लिए बजटीय उपबंध भी करा दिया है । महोदय, मैं हर रोज २-४ कलक्टर को टेलिफोन करता हूँ, हमने हर कलक्टर को यह जिम्मेवारी दी है कि जो प्रोवीजन किये गये हैं, वे लोगों को उपलब्ध हों, यह आपकी पर्सनल जिम्मेवारी है । मैं कहूँगा कि जिस कलक्टर ने इसमें रूचि दिखाई है, इंटेरेस्ट लिया है वहाँ पर यह व्यवस्था जल्दी लागू हुई है । महोदय, और भी प्रयास चल रहा है कि हर जगह के लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो ।

महोदय, सारे स्वास्थ्य सेवाओं को एक जगह से नियंत्रित करने के लिए हेल्थ विभाग ने अपना एक बेवसाईट कायम किया है । इसमें हमारे जितनी भी स्वास्थ्य सेवायें हैं, उनसे जुड़े हुये जितने लोग हैं उनको कम्प्यूटर से जोड़ा गया है, डॉक्टरों की नियुक्ति को इससे जोड़ा गया है, कौन डॉक्टर कहाँ कार्यरत हैं, इसको जोड़ा गया है, रोजाना कहाँ किस डॉक्टर का रोस्टर है, इसको भी जोड़ा गया है । महोदय, इस तरह से हम डॉक्टरों को ज्यादा नियंत्रित कर पायेंगे ।

महोदय, स्थिति में सुधार हुआ है । मैं मानता हूँ कि स्थिति जितनी बिगड़ी हुई थी, उसको रास्ते पर लाने के लिए थोड़े और समय की जरूरत है, जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, सरकार का डिटरमिनेशन है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सही ढंग से गरीबों को हम उपलब्ध करायेंगे ।

इसके अलावे माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बताया है कि हमने नया सदर अनुमंडल अस्पताल बनाया है, सदर अनुमंडल में जहाँ हमें उत्क्रमित करना है, अनुमंडल जहाँ हमें नया बनाना है और जो वर्तमान में हैं, उनको उत्क्रमिक करना है । नया बनाने वाले को हमने ५ करोड़ दिया है और उत्क्रमिक करने वालों को ९५ लाख दिया है । इसी तरह से डॉक्टर और पारा-मेडिक्स की कमी के बारे में हमने बताया और इसको दूर करने के उपाय भी बताये ।

इसके अलावे हम मोबाईल सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारी सेवायें उन दूर-दराज इलाकों के लिए होंगी जहाँ के लोगों को आम तौर से स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध नहीं हैं । हम अभी तत्काल इससे ३८ जिलों को ३८ मोबाईल वैनों के द्वारा शुरू करने जा रहे हैं लेकिन हमारा विचार है और आगे ऐसा किया भी जायेगा कि जो अपेक्षाकृत बड़े जिले हैं, वहाँ एक मोबाईल वैन से काम नहीं चलेगा, वहाँ एक से ज्यादा मोबाईल वैन की व्यवस्था की जा सकेगी । महोदय, सभी तरह की सुविधा उस वैन में रहेगी, डॉक्टर रहेंगे, उसमें एक कामचलाऊ ओ०टी० रहेगा, जाँच की सुविधा, इम्युनाइजेशन की सारी सुविधा होगी, उसमें कम्पाउंडर रहेंगे, ड्रेसर रहेंगे और उसमें जो सारे बेसिक दवाईयाँ हैं, वे भी उपलब्ध रहेंगी ।

...क्रमशः...

टर्न-५०/आजाद/९.३.२००६

श्री चन्द्रमोहन राय,मंत्री : (क्रमशः) और हम यह समझते हैं कि आगामी एक महीने के अन्दर हम इस मोबाईल सेवा का शुरुआत कर पायेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत माननीय सदस्यों ने दवा की अस्पतालों में कमी का जिक्र किया । मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, क्योंकि पिछली सरकार ने जिस प्रकार से दवा खरीद के नाम पर घोटाला किया, कोई भी कलक्टर जो जिला लेवल पर दवा क्रय समिति बनी थी, वे दवा खरीदने के लिए तैयार नहीं थे और घोटाले की वजह से दवा की आपूर्ति बन्द हो गई थी । लेकिन हमने कुछ दिन पहले राज्य स्वास्थ्य समिति की माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें हमने सारे बिहार के लिए क्रय नीति तय की है । उसमें हमने पूरे राज्य स्तर पर टेंडर आमंत्रित भी कर दिया है । जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, रिपुटेबुल कम्पनियां, उसी को हमने उसमें शामिल किया है और उनसे हम रेट तय करेंगे दवाओं का । उनसे हम रेट तय करके उन रेटों पर पटना में , यदि संभवतः जरूरी हुआ तो भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में भी गोदाम में बाध्य करेंगे दवाओं को रखने के लिए और सिविल सर्जन को आवंटन दे दिया है दवाओं के क्रय का और हमारी जो समिति होगी, वह टेंडर के द्वारा तय करेगी दवाओं का दर, उस आधार पर सिविल सर्जन उन कम्पनियों से क्रय करके और बाकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं की व्यवस्था करेंगे । मैं समझता हूँ कि आगामी २-३ महीनों में दवाओं अपनी जगह पर सब जगह चली जायेगी ।

आप जानते हैं अध्यक्ष जी कि आज हमारे लड़के करोड़ों रु० खर्च करते हैं, वे महाराष्ट्र जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, नोयडा तक जाते हैं और हमारे यहां मेडिकल कॉंसिल के द्वारा मान्यता दिये जाने के बाद भी सीटें कम कर दी गई । मात्र ३९० सीट है सरकारी मेडिकल कॉलेजों में । इसीलिए हमने निजी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला लिया है । ७ जगहों को हमने चिन्हित किया है और वहां से हमको ऑफर भी मिलने शुरू हो गये हैं । सरकार ने उसके लिए प्रोत्साहन नीति भी तय की है । इसके अलावा हम छोटे-छोटे बीमारियों के लिए दिल्ली दौड़ते हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप के आधार पर हमने पूरे बिहार में खासकर के पटना में सुपर स्पेशीलिटी होस्पिटल बनाने का निर्णय लिया है । इसके लिए भी हमें ऑफर मिलने शुरू हो गये हैं और तत्काल जयप्रभा होस्पिटल को हमने चिन्हित किया है और जो सरकारी होस्पिटल है, उसमें पटना का गुरु गोविन्द सिंह होस्पिटल, गया का पीलग्रीम होस्पिटल प्राइवेट हाथों में देने का फैसला किया है एक सुपर स्पेशीलिटी होस्पिटल के रूप में विकसित करने का ।

अध्यक्ष महोदय, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अवधारणा से आप परिचित होंगे । ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें बढ़ाने का यह कार्यक्रम है । केन्द्र सरकार से हम पूरा सहयोग कर रहे हैं । आगे आने वाले समयों में कुछ क्रांतिकारी कार्य शुरू हो रहा है । हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हर जगह २४ आवर्स लेबर रूम खोलने जा रहे हैं और चूँकि हम जानते हैं कि सरकारी क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी है । इसीलिए हम निजी चिकित्सकों से सहायता लेंगे डिलीवरी के लिए और निजी चिकित्सक को भी प्रति डिलीवरी हम अपने तरफ से १५०० रु० उस लेडीज डाक्टर को देंगे और वह डिलीवरी रूम, लेबर रूम जो है, वह २४ घंटा कार्यरत रहेगा और इसको हम जनहित सुरक्षा के रूप में भी दे रहे हैं । एक मामला उठाया, जिसको लेकर वाकआऊट किया, एक टी०वी० चैनल ने स्टींग ऑपरेशन के द्वारा कुछ डाक्टर पर यह आरोप लगाये हैं कि वह सेक्स डिटरमीनेशन करके अगर वह भ्रुण कन्या निकलती है तो उसकी हत्या होती है । यह एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय, थोड़ी है । कानून में तो यह प्राप्त है ही, समाज के दृष्टि से भी , समाज के लिए यह एक अक्षम्य अपराध है । अगर सबूत मिला तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के अन्दर ही नहीं, मैं यहां तक कह रहा हूँ कि अगर डाक्टर के खिलाफ यह साबित हो गया, चाहे वह कितना बड़ा ही डाक्टर क्यों न हो तो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराकर के उसके प्रेक्टिस को हमेशा के लिए बन्द किया जा सकता है ।

इसके अलावा हमने पी०एम०सी०एच० को, आप जानते हैं एक जमाना में बहुत बड़ा होस्पिटल पूरे पूर्वी क्षेत्र में दूसरे-दूसरे राज्यों से भी लोग यहां इलाज कराने के लिए आते थे । कालान्तर में लगातार इसकी अवनति होती चली गई , कारण सुनने के लिए लोग नहीं है । आप सब लोग जानते हैं लेकिन आज पी०एम०सी०एच० में कुछ दिन पहले मेडिकल कॉंसिल ऑफ इंडिया की एक टीम आयी थी और उसने एक मेडिकल कॉलेज को छोड़ करके सभी मेडिकल कॉलेज की जो अर्हताएं हैं, उसमें कमी पाया था और उनको भी डी-रिकॉगनाईज करने का श्रेट दिया था । आपको जानकर खुशी होगी और मैं विधान सभा को बताना चाहता हूँ कि अगले जुलाई महीना में फिर वह टीम आने वाली है उसको एक्जामीन करने के लिए और जिन-शर्तों को उन्होंने लागू किया था, पूरा करने के लिए कहा था, उन सारे शर्तों को या तो पूरा कर लिया गया है और जो बाकी है, उसके लिए पैसे का प्रबंध कर दिया गया है और आगामी दो महीनों में सारी शर्तें पूरी कर दी जायेगी और जुलाई महीने में जब हमारी टीम आयेगी तो हमारे सभी मेडिकल कॉलेज की सारी शर्तें पूरी हो जायेगी

टर्न-५१/अंजनी/दि० ०९.०३.०६

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आसन की तरफ मुखातिब होकर बोलें ।

श्री चन्द्रमोहन राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना- ही बात कहना चाहता हूँ कि आज हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पहल की है, आज स्वास्थ्य सेवा के सुधार के संबंध में एक युगन्तकारी काल के कागार पर बिहार खड़ा है । उसके परिणाम आगामी कुछ दिनों में आपको देखने में आयेंगे चाहे वह स्वास्थ्य सेवा के हों, चिकित्सा शिक्षा के रूप में हो, सुपर स्पेसिलिटी के क्षेत्र में हो या गरीबों की चिकित्सा के संबंध में हो । महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का सुझाव है, बहुत-से लोगों ने मुझसे कहा था कि गरीब लोगों को इलाज कराने में चिकित्सा फंड की कठिनाई आ रही है । माननीय मुख्यमंत्री जी के सुझाव पर मैंने पहल करना शुरू कर दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक चिकित्सा कोष का गठन किया जायेगा, जिसमें माननीय विधायकों और लोगों के अनुशंसा पर लोगों के इलाज के लिए चिकित्सा फंड उपलब्ध कराया जायेगा । अब वह शिकायत भी नहीं रह जायेगी, जिसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने की थी । वह समस्या आगामी कुछ दिनों में दूर हो जायेगी । अभी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से जो फंड है, उसमें आनेवाली जो कठिनाईयाँ हैं, उन कठिनाईयों को भी सरल बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ताकि ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके । कुछ माननीय सदस्यों ने आयुर्वेदिक या देशी चिकित्सा पद्धति की चर्चा की, आज जो हमारी स्वास्थ्य नीति है, उसका एक प्रमुख अंग है । आयुर्वेदिक डाक्टरों की बहाली हो रही है । यहाँतक कि पी०एम०सी०एच० में आयुर्वेदिक डाक्टरों की बहाली हो रही है । मैं इस बात को मानता हूँ कि यह चिकित्सा पद्धति अपेक्षाकृत सस्ती है और बहुत तरह की बीमारियों के लिए काफी फायदेमंद भी है । सरकार सभी तरह की उपाय करेगी इस चिकित्सा सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उसके लिए हम आगामी आनेवाले समय में जहाँ-भी पद रिक्त हैं, उनको भरे जायेंगे । कुछ पद सृजित भी किये जा रहे हैं आयुर्वेदिक डाक्टरों की, यूनानी डाक्टरों की, हकीमों की, वैद्यों की बहाली करके, हैम्योपैथिक डाक्टरों की बहाली करके माननीय सदस्यों ने जो इशारा किया है, उस वैक्लिपक चिकित्सा व्यवस्था की लागू करने का कोशिश करेंगे । इतना-ही बात कहकर माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि आप सर्वसम्मति से बजट को पास कर दीजिए ताकि बिहार में स्वास्थ्य सेवा के बेहतरी का मार्ग प्रशस्त हो ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री जगदानन्द सिंह, अपना कटौती-प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री जगदानन्द सिंह सदन में अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि -

"इस शीर्षक की मांग १०/- (दस) रुपये से घटायी जाय ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

प्रश्न यह है कि -

"स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" के संबंध में ३१ मार्च, २००७ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए १०,८३,३०,१८,०००/- (दस अरब तेरासी करोड़ तीस लाख अठारह हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

आज दिनांक ०९.०३.०६ के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या ३१ है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिये जायें ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक १० मार्च, २००६ को ११.०० बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।